



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 1993/JYAIKSHANA 11, 1915

No. 320]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 1993/JYAIKSHANA 11, 1915

लोक सभा सचिवालय

तथा

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1993

श्री श्रीकान्त जैना द्वारा (एक) सर्वथी अजित सिंह, रणीद मसूद, हरपाल पंचार तथा सत्यपाल सिंह यादव तथा (दो) सर्वेश्वरी राजनाथ सोनकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध तथा शिवशरण वर्मा, संसद मदस्यों के विश्वदायर दो मंत्रित याचिकाओं के विषय में।

का.आ. 350 (अ) :—भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत लोक सभा अध्यक्ष का दिनांक 1 जून, 1993 का निम्नलिखित विनियम एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

तथा

“माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष

7 अगस्त, 1992 को जनता दल विधान मंडल दल के 20 मदस्यों द्वारा दायर आवेदन के विषय में

तर्क के मुख्य मुद्दे

तथा

1. जनता दल के 59 सदस्य दसवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। श्रो. बी.पी. मिह जनता दल संसदीय दल के नेता थे।

2. 7-8-1992 को सर्वेश्वरी राम लखन सिंह यादव, राम शरण यादव, राम सुन्दर दास, उपेन्द्र नाथ वर्मा, सूर्यनारायण यादव, गोविन्द चन्द्र मुंडा, श्रनादि चरण दास, अजित सिंह, रणीद मसूद, हरपाल पंचार, अभग प्रताप मिह, गुलाम मोहम्मद खां, राम निहोर राय, राम बदन, राम अवध, आर. सोनकर शास्त्री, शिवशरण वर्मा, सत्यपाल सिंह यादव, अर्जुन सिंह यादव तथा रोशन लाल ने अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें कहा गया कि उन्हें लोक सभा में अलग सीटें दी जाए। इस पर “डी-1” चिन्हित किया गया है।

तथा

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सर्वेश्वरी श्रनादि चरण दास, सूर्यनारायण यादव, राम लखन सिंह यादव, राम शरण यादव, रोशन लाल, अर्जुन सिंह यादव, अभग प्रताप सिंह तथा उपेन्द्र नाथ वर्मा, संसद मदस्यों के विश्वदायर आठ याचिकाओं के विषय में

3. इस आवेदन पत्र पर लोकसभा के उपरोक्त 20 सदस्यों के हस्ताक्षर थे तथा चार अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर थे। ये चार हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष को आवेदन पत्र देते समय उन 20 सदस्यों के साथ नहीं गए थे।
4. इन 20 सदस्यों को आवेदन पत्र पर पुनः हस्ताक्षर करने को कहा गया ताकि इस बात की पुष्टि को जासके कि उन्होंने स्वेच्छा से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
5. उक्त आवेदन पत्र को एक फोटो प्रति श्री वी.पी. सिंह के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई।
6. श्री वी.पी. सिंह ने अपना लिखित वक्तव्य 11-8-92 को भेजा।
7. उनके लिखित वक्तव्य में सारतः निम्नलिखित बातें कहीं गयीं थीं :

(एक) सर्वश्री अंजित सिंह, रगोद मसूद, हरपाल पंवार तथा सत्यपाल सिंह यादव सभी लोक सभा सदस्यों को जनता दल के अध्यक्ष श्री एम. ग्रार. बोमर्ड द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। श्री अंजित सिंह को 26-12-1991 को निष्कासित किया गया था। तीन अन्य सदस्यों को जनवरी, 1992 के माह में निष्कासित किया गया था।

(दो) सर्वश्री ग्रार. मोहकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध तथा शिव गरण वर्मा, सभी लोक सभा सदस्यों को जनता दल के अध्यक्ष श्री एम. ग्रार. बोमर्ड द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से 19-7-1992 को निष्कासित किया गया था।

(तीन) इसलिए उपरोक्त आठ सदस्यों को जनता दल विधान मंडल पार्टी की सदस्यता भी समाप्त हो गई।

(चार) इसलिए ये सदस्य उन 20 सदस्यों के गुप्त का अंग नहीं बन सकते जो अपने मूल दल अथवा जनता दल से अलग होता चाहते हैं।

(पांच) सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुंडा, गुलाम मोहम्मद खां तथा राम बदन सभी लोक सभा सदस्यों ने उन विहितों का उल्लंघन किया जो 17-7-1992 को सरकार विशद्व पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए उन्हें जारी किये गये थे। भारत के संविधान को दसवीं अनुसूची के नियम 2(1) (ख) के उपबन्धों के अधीन वे निरहू हो गए हैं तथा 17-7-1992 से वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं।

(छह) इस प्रकार 20 सदस्यों में से 12 सदस्य निरहू हो गए थे और लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।

(सात) सर्वश्री रामशरण यादव, अभय प्रनाल मिह, रामलक्ष्मन मिह यादव, अनादि चरण दास, गोशन लाल, अर्जुन मिह यादव, उपेन्द्रनाथ वर्मा और सूर्य नागरण यादव—लोक सभा के ये सभी आठ सदस्य जनता दल संसदीय दल के एक निरहू सदस्यों का ग्रुप नहीं बना सके जो भारत के मंविधान को दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के उपबन्ध के अनुसार जनता दल से प्राप्त हो सके। वे सभी दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अधीन निरहू हुए, और 7-8-1992 से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे।

(आठ) इसलिए, उपर्युक्त 20 सदस्यों का आवेदन अम्बीकृत किया जाना चाहिए।

8. दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के निवंधनों के अनुसार श्री विश्वनाथ प्रताप मिह, ने सर्वश्री गम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुंडा, गुलाम मोहम्मद खां और राम बदन, सभी लोक सभा सदस्यों, के विशद्व 11-8-1992 को याचिकाएं दायर की।

9. सार रूप में, याचिकाओं में संगत मुद्दे एक समान हैं। वे इस प्रकार से हैं :

(एक) प्रत्ययियों को सरकार के विशद्व पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने का निर्देश दिया गया था।

(दो) 17-7-1992 को उपर्युक्त प्रस्ताव पर भतदान हुआ।

(तीन) प्रत्ययियों ने भतदान में भाग नहीं लिया और उन्हें जारी किए गए विशद्व का स्वेच्छा से उल्लंघन किया।

(चार) इसलिए, वे निरहू हो गए और 17-7-1992 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।

(पांच) याचिकादाता ने इस आशय को घोषणा करने की मांग की।

10. प्रत्ययियों ने 19-8-1992 को अपने निखिल वक्तव्य दायर किए।

सार रूप में उन्होंने कहा कि :

(एक) उन्होंने विशद्व का उल्लंघन स्वेच्छा से नहीं किया था।

- (दो) उन्होंने प्रस्ताव पर पार्टी के निदेशानुसार मत देने का प्रयास किया था।
- (तीन) परन्तु, प्रत्येक लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में दिए गए कारणों की बजाए से वे उन्हे जारी किए गए विवरों का पालन नहीं कर सके।
- (चार) उनके कार्य अनंतिक थे आर इमलिए, उन्हें निरर्हित नहीं किया जा सकता था।
11. श्री राम सुन्दर दाम ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में सार रूप में कहा है कि—
- (एक) अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान बाने दिन वह संसद ग्रन्थालय में आराम कर रहे थे क्योंकि रस्तवाप के कारण उनकी तबियत ठीक नहीं थी।
- (दो) जब मन विभाजन घटी बजी तो वह लोक सभा कक्ष की ओर दौड़े।
- (तीन) तथापि, जिस समय वह लोक सभा कक्ष में प्रवेश-न्वार तक पहुंचे उम गमय द्वारा बंद हो चुके थे और वह कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके।
- (चार) वह प्रस्ताव के पश्च में मतदान करना चाहते थे लेकिन वह नहीं कर सके।
- (पाच) मतदान न करने का उनका कार्य अनंतिक था।
- (छह) अतः वह निरर्हित नहीं किये जा सकते।
12. श्री गोविंद चन्द्र मुंडा ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में, सारांश में, कहा है कि—
- (एक) वह 15, 16 और 17 जुलाई, 1992 को स्वस्थ नहीं थे और स्वॉइकल स्पोषिटिवाइटिस के कारण गर्दन और शरीर में तीव्र दर्द से पीड़ित थे।
- (दो) 17-7-1992 को उन्होंने लोक सभा के प्रातः कालोंत मन्त्र में भाग लिया। लेकिन दोपहर बाद वह अस्वस्थ होने के कारण अपने घर चले गये और उन्होंने कुछ हूर्वत श्रीयदि ली जिससे वह मूर्चित हो गये।
- (तीन) वह प्रस्ताव पर मतदान करना चाहते थे। उन्होंने अपने दल के नेता को मूर्चित किया था कि यदि सभा में मतदान के लिए उनका उपस्थिति अपेक्षित है तो उन्हें प्रस्ताव पर मतदान बरने के लिए डाक्टर की अनुमति से एम्बुलेन्स में लोक सभा ले जाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
- (चार) उनका मतदान १३ अनुपस्थित रहना अनंतिक था।
- (पांच) अतः वह निरर्हित नहीं किये जा सकते।
13. श्री गुलाम मोहम्मद खां ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा संख्या 11 में, सारांश में, कहा है कि—
- (एक) वह भव्यमेह और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे और वह 17-7-1992 को और उससे दो दिन पहले तक स्वस्थ नहीं थे।
- (दो) उन्हें राम मनोहर लोहिथा अस्पताल में भर्ती किया गया था और 17-7-1992 को वह अस्पताल में थे।
- (तीन) वह प्रस्ताव पर मतदान करना चाहते थे।
- (चार) अतः उन्होंने दल के नेता को सूचित कर दिया था कि यदि सभा में उनकी उपस्थिति जरूरी है तो उन्हें डाक्टर की अनुमति से सभा में ले जाया जा सकता है।
- (पांच) मतदान न करने का उनका कार्य अनंतिक था।
- (छह) अतः वह निरर्हित नहीं किये जा सकते।
14. श्री राम बदन ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में कहा है कि—
- (एक) वह 17-7-1992 को लोक सभा में उपस्थित थे और उन्होंने प्रस्ताव के समर्वतन में बटन दबाया था।
- (दो) उनकी नजर कमजोर है। अतः वह बोर्ड की तरफ देख कर यह पता नहीं लगा सके कि उनका बोट सही ढंग से रिकार्ड हुआ है या नहीं।
- (तीन) उन्होंने सभा में परिचर से, जो सदस्यों को अपने गलत रिकार्ड किए गये बोट में शुद्धि करने के लिए पर्चियां दे रहा था, पूछा था कि क्या उनका बोट रिकार्ड हो गया है। परिचर ने उन्हें सूचित किया था कि उनका बोट रिकार्ड हो गया है।
- (चार) बाद में उन्हें पता चला कि उनका बोट रिकार्ड नहीं हुआ है।
- (पाच) वह प्रस्ताव के पश्च में मतदान करना चाहते थे।
- (छह) उन्होंने स्वैच्छिक रूप से विहंग का उल्लंघन नहीं किया था।

(सात) अतः वह निर्रहित नहीं किये जा सकते।

15. दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के मंबंध में श्री बी पी. सिंह ने 22-8-1992 को सर्वश्री राम शरण यादव, अभय प्रताप सिंह, रामलक्ष्मन सिंह यादव, अनादिचरण दास, गोपन लाल, मर्जुन मिह यादव, उपेन्द्रनाथ वर्मा तथा सूर्य नारायण यादव, सभी लोक ममा के सदस्य, के विरुद्ध आठ याचिकाएं प्रस्तुत की।

16. सारांश में, प्रतिवादियों के नामों को छोड़कर, याचिकाओं का विषय एक समाप्त है तथा प्रतिवादियों के नाम इस प्रकार हैं —

(एक) सर्वश्री अर्जित सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पवार, मत्यपाल सिंह यादव, आर. सोनकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध और शिवशरण वर्मा को पार्टी अध्यक्ष थीं एम.आर. बोमरई द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता में निष्कासित कर दिया गया था। अत उन्होंने विधानसभा दल की अपनी-अपनी सदस्यता खो दी थी। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया।

(दो) सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुण्डा, गुलाम मोहम्मद खान तथा राम बदन ने 17-7-1992 को उन्हें जारी किये गये विहित का उल्लंघन किया था तथा इसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अधीन निर्रहित हो गए थे और 17-7-1992 में लोक ममा के सदस्य नहीं रहे। उन्होंने दूसरा ग्रुप बना लिया।

(तीन) आठ प्रत्यर्थियों ने तीसरा ग्रुप बना लिया।

(चार) तीन ग्रुप एक ऐसा संयुक्त ग्रुप नहीं बना सके जिसमें वे निर्रहित हुए बिना जनता दल में शामिल हो सके।

(पांच) प्रत्यर्थी दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क) (1) में उपर्युक्त उन्मुक्ति का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि 7-8-1992 को उनकी संख्या जनता दल के 51 सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई नहीं थी क्योंकि निष्कासित किये गये आठ सदस्यों को तथा उन चार सदस्यों को जो 17-7-1992 से लोक ममा के सदस्य नहीं रह गये थे, उनके साथ ग्रुप में नहीं गिना जा सका था।

(छ) जैसा कि अपेक्षित है, जनता दल का संसद के बाहर विभाजन नहीं हुआ था, जिसमें जनता दल विधान संडल दल का विधिक रूप में विभाजन हो सके।

(सात) याचिकादाता ने इस आशय की घोषणा करने की प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी निर्रहित हो गये हैं तथा 7-8-1992 से लोक ममा के सदस्य नहीं रहे हैं।

17. प्रत्यर्थियों ने 31-8-1992 को अपने-अपने लिखित वक्तव्य दाखिल किये।

18. मार रूप में उनमें यह कहा गया है कि :

(एक) संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार दल के नेताओं द्वारा आठ सदस्यों को निष्कासित नहीं किया जा सका।

(दो) चार सदस्यों ने स्वेच्छा से मतदान में भाग नहीं लिया तथा स्वेच्छा में विहित का उल्लंघन नहीं किया था तथा लोक ममा में उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई थी।

(तीन) 7-8-1992 को जनता दल विधान संडल दल के 59 सदस्य थे।

(चार) 7-8-1992 को जनता दल विधान संडल दल विभाजित हो गया था।

(पांच) जिन 20 सदस्यों ने एक ग्रुप बनाया था तथा जो जनता दल विधायक दल की सदस्य-संख्या के एक-तिहाई से अधिक थे, और जिन्होंने अन्तर्गत बैठने की अनुमति मारी थी, तथा दल में विभाजन किया था, वे अनहंता के पात्र नहीं थे तथा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क) (एक) के उपर्युक्त को देखते हुए लोक ममा के सदस्य बने रहे।

(छ) अर्जित सिंह गुट ने मूल जनता दल होने का दावा किया।

(सात) अत याचिकाये अस्वीकार की जानी चाहिये थीं।

19. लोक ममा सदस्य तथा जनता दल के संसदीय दल के ग्रुप सचेनक थी थीकान जैना ने 3-10-1992 को दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) तथा पैरा 6 के अधीन सर्वश्री अर्जित सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पवार और मत्यपाल सिंह यादव के विरुद्ध एक याचिका दायर की।

20. संक्षेप में, याचिका में उठाई गई मुख्य बातें हैं—

(एक) प्रतिवादियों ने दावा किया कि 5-2-1992 को जनता दल का विभाजन हुआ था और थी अर्जित सिंह के नाम का दल के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदन किया गया।

(दो) जब 5-2-1992 को विभाजन हुआ, तो इसमें लोक ममा के केवल चार सदस्य थे जो दल को विभाजित करने वाले ग्रुप के सदस्य थे।

- (तीन) भारत के संविधान की दसवीं अनुमूल्ची के पैरा 3(क) (एक) के अध्ययन उन्मुक्ति पाने हेतु चार सदस्य, लोक सभा मे जनता दल के सदस्यों के एक-तिहाई के बनावर नहीं थे।
- (चार) जनता दल के चार सदस्य अनर्हता के पाव्र हो गए तथा छिप का उल्लंघन करने के कारण 17-7-1992 को लोक सभा मे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है।
- (पाच) याचिकादाता ने कहा था कि चार प्रतिवादियों तथा चार अन्य सदस्यों को जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया था और इस प्रकार समद मे जनता दल की उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी।
- (छ) प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए लिखित वक्तव्यों तथा चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए वक्तव्यों मे की गई इम स्पष्ट स्वीकृति को ध्यान मे रखते हुए कि उन्होने 5-2-1992 को पार्टी का विभाजन किया था, याचिकादाता प्रार्थना करता है कि यह घोषणा की जाए कि प्रतिवादी अनर्हता के पाव्र हो गए तथा 5-2-92 ने लोक सभा मे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई।
21. प्रतिवादियों ने 4-11-1992 को अपना लिखित वक्तव्य दिया।
22. साराण मे प्रतिवादियों का कहना है कि —
- (एक) याचिकादाता को अनुमोदन तथा निरन्मोदन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- (दो) याचिकादाता यह नहीं कह सकता कि प्रतिवादी जनता दल तथा जनता दल संसदीय दल के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हे दल मे निकाल दिया गया था और कि उन्हे अनर्ह घोषित किया जाए तथा 5-2-1992 से लोक सभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए।
- (तीन) प्रतिवादियों का ग्रुप वास्तविक जनता दल है और इसलिए समद मे दल के सर्व सदस्य उनके ग्रुप मे संबंधित हैं, जब तक कि वे विशेष व्यप से अन्यथा घोषणा नहीं करते।
- (चार) प्रतिवादी याचिका मे दी गई अन्य बातों मे इनकार करते हैं।
- (पाच) प्रतिवादी प्रार्थना करते हैं कि याचिका खारिज की जाए।
23. 3 अक्टूबर, 1992 को लोक सभा सदस्य तथा जनता दल संमिश्र पार्टी के मुख्य सचेतक श्री थीकात जेता ने भारत के संविधान की दसवीं अनुमूल्ची के पैरा 2(1) (क) के मदर्म मे सर्व श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, रामनिहोर गाय, नाम अवध तथा शिव शरण वर्मा, के घिन्नद्व एक याचिका दायर की।

24. याचिकादाता के कहने का सार यह है कि-
- (एक) श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों को, जो इस सामने मे प्रतिवादी हैं, दल से निकाल दिया गया थ.;
- (दो) श्री राम मुन्दर दास और तीन अन्य सदस्यों ने विहिप का उल्लंघन किया थ. और इसलिए वे अनर्हता के पाव्र हो गये और 17 जुलाई, 1992 मे वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।
- (तीन) श्री अजित सिंह तथा अन्य सात सदस्यों ने स्पष्ट शब्दो मे यह दावा किया कि 5 फरवरी, 1992 को उनका जनता दल से विभाजन हो गया था और उनका सबध उस घटक मे है जो अमली जनता दल है। यह दावा उन्होने अपने द्वारा दिये गए लिखित बयानो मे तथा चुनाव आयोग के समक्ष दिये गए बयानो मे किया था।
- (चार) इस प्रकार श्री अजित सिंह और तीन अन्य समद सदस्यों ने संविधान की दसवीं अनुमूल्ची के पैरा 3(क) के अनुसार पृथक दल का गठन किया था।
- (पाच) 7 अगस्त, 1992 को 20 समद सदस्यों ने लोक सभा अध्यक्ष वा एक आवेदन पत्र दिया जिसमे उनके दल से अलग होने की घोषणा करने और उन्हे लोक सभा मे बैठने के लिए पृथक स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था।
- (छ.) चूंकि श्री अजित सिंह तथा तीन अन्य समद सदस्यों ने एक पृथक दल का गठन कर लिया था इसलिए वे जनता दल के उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकते थे जो मूल जनता दल से अलग हुआ था।
- (मात्र) शेष 16 सदस्य संसदीय जनता दल के एक तिहाई सदस्यों का ग्रुप नहीं थे। अतः वे अनर्हता के पाव्र हो गये।
- (आठ) इस तरह प्रतिवादी अनर्हता के पाव्र हो गये तथा वे दसवीं अनुमूल्ची के पैरा 3(क) (एक) के अनुसार उन्मुक्ति प्राप्त न करने के कारण उसी अनुमूल्ची के पैरा 2(1) (क) के अनुर्गत 7 अगस्त, 1992 मे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।
25. प्रतिवादियों ने 4 नवम्बर, 1992 को अपने लिखित बयान दायर किए।
26. संक्षेप मे, प्रतिवादियों का कहना है कि—
- (एक) याचिकादाता को अनुमोदन करने तथा निरन्मोदन करने की अनुमति न दी जाए।
- (दो) वे दसवीं अनुमूल्ची के पैरा 3(क) (एक) के अनुर्गत उन्मुक्ति का बाबा करते हैं।

- (तीन) जनता दल के जिम घटक के बैंग मदम्य हैं वही अपनी जनता दल हैं तथा इस तरह ससद में जनता दल के सभी मदम्य उनके घटक के मदम्य हैं जब तक कि वे अत्यधा दावा न करें।
- (चार) अन्य मदम्यों द्वारा विहृप वा उल्लंघन करने के कारण उन्हें दल से निकाले जाने तथा अन्य ठहराने सवधी सभी बातें तथा अन्य बातों का भी ठन्कार किया जाता है।
- (पाच) प्रतिवादी प्रार्थना करते हैं कि याचिका खारिज की जाए।
- कार्यवाही किस तरह संचालित की गई थी?**
- 27 20 मदम्यों द्वारा दिया गया आवेदन तथा श्री बी पी मिह द्वारा दायर की गई 12 याचिकाओं तथा श्री श्रीकान्त जेना द्वारा दायर 2 याचिकाओं से कही बाने एक जीर्ण है। अत पक्षकारों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि सभी याचिकाओं तथा आवेदन पर एक साथ मुनबाई की जाएगी तथा निर्णय लिया जाएगा।
- 28 विवाद के पक्षकारों को अपने मुकदमों की स्वयं तथा अपने वकीलों के माध्यम से पैशवी करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपने अभिवादन दायर किए, गवाहों में पूछनाल की तथा अपने वकीलों के माध्यम से बहस की जिन्होंने कानून के बिन्दओं और तथ्यों पर अपना कार्य अन्युलम, सदमावपूर्ण एवं त्यागोचित ढंग से किया।
29. मोटे तंत्र पर सिविल प्रक्रिया सहित का पालन कार्यवाही चलाने में किया गया।
- 30 जहा कही भी मिथिल प्रशिक्षा, सहित का पालन नहीं किया जा सका उस स्थिति में स्वाभाविक त्याय के मिदातों का पालन किया गया।
31. लोक सभा में राजनीतिक दलों के नेताओं को कानूनी मुद्दों पर मौखिक रूप से और साथ ही लिखित रूप से अपना भत व्यक्त करने वी अनुमति दी गई थी।
- 32 कार्यवाही को देखने और समावरण पत्रों तथा प्रचार माध्यम द्वारा इसे प्रकाशित एवं प्रमाणित करने वी अनुमति दी गई थी।
- 33 पक्षकार द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष विस्तृत किए गए।
34. पक्षकारों के वकीलों ने विस्तृत दलीलें पेज की जो 20 घटे तक जारी रहीं।
- 35 साक्ष एवं दलीलों का शब्दांश रिकार्ड किया गया। वे आडियो कैसेट के रूप में भी उपलब्ध हैं।
- 36 अभिवचनों साथ्यों, एवं दलीलों की पुस्तिकाओं के रूप में सञ्चित किया गया है।

37 मामले से सबधित मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया और उस पर माश्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई और दलीले मूरी गईं।

38 पक्षकारों को मूरने के बाद मामले से सबधित मददों को अतिम रूप दिया गया। तथापि, बहुप कर्ता समय पक्षकार मामले में सबधित मुद्दों पर दृष्टिगति कायम नहीं रहे।

बाद के पैराप्राप्ता में दिए गए तिर्फ में मुददा के निकर्पों को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

### मुददे

#### दस्तावेज़ ‘डी१’ से सबधित मुददे

- (एक) क्या भारत के सविधान किसी अन्य कानून अवधा लाक सभा के प्रक्रिया मबदी नियम के अन्तर्गत दस्तावेज़ ‘डी१’ दायर किया गया है?
- (दो) हस्ताक्षरकर्ता ‘डी१’ के अन्तर्गत का दायर करने हैं?
- (तीन) भारत के सविधान रो इसी अनुसूची के अन्तर्गत दायरे के बाब और किस प्रकार से मिछु किये जायेगे?
- (चार) क्या किसी गजनीतिक दल का नेता अपने दल के किसी मदम्य को पार्टी से नियमासित कर सकता है और विधायी दल की उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जिसमें भारत के सविधान, अन्य कानूनों अधिवा लोक सभा के प्रक्रिया सबधी नियमों के अन्तर्गत मदम्य को प्राप्त उसके अधिकार, दायित्वा और उन्मुक्तियों में परिवर्तन हो सके?
- (पाच) मदम्यों को उनके दल में नियमासित किये जाने के बाद उनके दल के नेता के कहों पर मदम्यों के पृथक बैठने का अमित्राय क्या है? क्या भारत के सविधान की दमदी अनुसूची शी डायला हास्ते तथा इसे प्रवर्तित करने से इसका कोई महत्व है?
- (छ) सदम्यों का अपने आप दल के मदम्यों से पृथक बैठने का क्या अमित्राय है। क्या भारत के सविधान की दस्ती अनुसूची की व्याख्या करने तथा इसे प्रवर्तित करने के लिए इसका कोई महत्व है?
- (सात) क्या आदेश किया जाए?
- विहृप के उल्लंघन से सबधित मुददे**
- (एक) क्या याचिकादाता यह मिछु करता है कि प्रतिवादी ने स्वेच्छा में विहृप का उन्नयन किया और यदि हाँ, तो क्या प्रतिवादी का 17-7-1992 स मदम्य की सदस्यता से विचित कर दिया गया?
- (दो) क्या प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि वह स्वेच्छा में भतदान से विरक्त नहीं रहा?

(तीन) क्या आदेश किया जाए?

स्वेच्छा में गजतैनिक दल की मदम्यता छोड़ने संबंधी मुद्दे

(एक) क्या धार्चिकादाता यह मिल्द करता है कि प्रतिवादी दस्तावेज "डी" पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत के संविधान की दमवी अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अन्तर्गत अनहै करार किये जाने योग्य हो गया है?

(दो) क्या प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि दसवी अनुसूची के पैरा 3 द्वारा उपलब्ध कराई गई उन्मुक्तियां उमे प्राप्त हैं?

(तीन) क्या आदेश किया जाए?

श्री अर्जित सिंह और तीन अन्य लोगों के मामलों से संबंधित मुद्दे

(एक) क्या धार्चिकादाता यह सिद्ध करता है कि जनता दल पार्टी का एक अलग गट गठित करके थी अर्जित मिह और तीन अन्य लोग भारत के संविधान की दमवी अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अन्तर्गत अनहै ठहराये जाने के योग्य हो गए हैं?

(दो) क्या प्रतिवादी यह मिल्द करते हैं कि दसवी अनुसूची के पैरा 3 द्वारा दी गई उन्मुक्तियां उन्हें प्राप्त हैं?

(तीन) क्या आदेश किया जाए?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य मदम्यों के मामले से संबंधित मुद्दे

(एक) क्या धार्चिकादाता ने यह प्रमाणित किया है कि श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्य दस्तावेज डी-1 के हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण भारत के संविधान की दमवी अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत अनहै हो गये हैं।

(दो) क्या प्रतिवादियों ने यह प्रमाणित किया है कि दसवी अनुसूची के पैरा 3 द्वारा प्रदान की गई खुट उन्हें उपलब्ध है?

(तीन) आदेश क्या दिया जाए?

कानूनी मुद्दे

39. कार्यवाहियों के दौरान कुल मिलाकर निम्नसिद्धित कानूनी मुद्दों पर चर्चा की गई।

दल बदल विरोधी कानूनों की किम प्रकार घायल की जाए

40. भारत के संविधान की दमवी अनुसूची को दल-बदल विरोधी कानून समझा जाता है और मूल्यवान् इसी रूप में हो जाना जाता है।

41. इस निर्वाचित जन प्रतिविधिया द्वारा विधान मंडल में इस वदन किये जाने के द्वारा पर शोष और नियन्त्रण करने के लिए बनाया गया है।

42. इसके अधिकार में आर्टे में पूर्व प्रिवादक अधिनी इच्छा से मन दें गहरे थे आर्टे दमों को छोड़ सकते थे और अन्य दलों में शामिल हो सकते थे और उन्हें उनकी विधान मंडल की विधायिका दमवी अनुसूची की जा सकती थी। उन्हें मात्र देने की, किमी बल में शामिल होने की अवधि कोई नहीं दी जाना चाहिए। उनकी विधायिका दमवी अनुसूची के समान ही था। अन्य देशों के समदर गद्दीयों की भी इसी प्रकार का अधिकार प्राप्त है।

43. नशापि अधिकार का दृष्टायोग किया गया था जो भवा इसका अनुचित नाम उठाया गया था। इसमा प्रयोग सरकारों को अस्थिर अनान तथा मनमाने प्रौद्योगिकी के समान ही था। अन्य देशों के लिए अन्य गद्दीयों था।

44. अन दल बदल के बने दो रोकते के लिए अन्यमान कानून बनाया गया।

45. इसमें विधायिकों के दायित्वों तथा अधिकारों की रचना होती है।

46. यह विधायिक दो व्यावेश देगा है कि उमे दल द्वारा जारी हित गए विड पर के अनुभाव मनदान करना है उमे आमा बल नहीं छोड़ता है किमी नए दल का गठन नहीं करना है और न ही किमी बल में शामिल होता है। यदि यह इन दायित्वों की अवधेतना करना है तो उमे अन्य विधान मंडल का मदम्यहोने से अनहै वोपिष किया जा भक्ता है। आग यह विधान मंडल की आर्टी मनमता यो सकता है।

47. ये दायित्व अपने आप में पूर्ण नहीं है। वही कानून इसमें कुछ नियायन भी देता है जिसमें इन दायित्वों की रचना होती है। यदि विधान मंडल में उमके बल के एक-तिहाई उगके माथ मिलकर दल द्वारा जारी किए गए निर्देश के विधीन मनदान करने की इच्छा रखते हैं तो वह उमे जारी किए गए विडप का उपलब्ध करने की इच्छानुसार मनदान कर भक्ता है। दल में विधायिकों की स्थिति में विधान मंडल में अपने दल के एक-तिहाई मदम्यों के माथ वह बल में अन्य दो सकता है और नए दल का गठन कर सकता है। आग उमे अनहै भी धोर्वित नहीं किया जा सकता। वह विधान मंडल में अपने दल के दो-तिहाई मदम्यों के माथ किमी भी अन्य दल में शामिल हो गया है और उमे पर अनश्वरा का कोई प्रावधान नापू तकी होता है। ये प्रतिवार उमे इनियर दिए गए हैं क्योंकि दमवी अनुसूची में अस्थिर से आर्टी में पड़ते ये उमे उपलब्ध थे और क्योंकि इसे प्रकार के अधिकार प्रजातात्तिक एवं मस्तीय प्रणाली में प्रावधान के लिए अधिकारों एवं दायित्वों का रचना करता है। उमका निर्वचन भा यहूत ही मानवानीपूर्वक तथा कराई से करना होता।

48. अन दसवी अनुसूची के प्रावधानों का निर्वचन अन्यतर मनकंसा-पूर्ण एवं कराई से करना होता।

49. यह धार्चिका बदू दी व्यापक निर्विधियों एवं अनेक सम्पादों और व्यक्तियों को प्रमाणित कर सकती है। जो कानून नागरिकों, तथा व्यक्तियों के एक वर्ग और कुणी प्रकार जूते गए जन प्रतिविधियों के लिए अधिकारों एवं दायित्वों का रचना करता है। उमका निर्वचन भा यहूत ही मानवानीपूर्वक तथा कराई से करना होता।

50. जो प्रावधान दमवी अनुसूची में नहीं है उमे इसम जामिल नहीं किया जा सकता।

51. दल के संविधान के उपवीं का दमवी अनुसूची में धार्चम और पर स्थापन नहीं किया जा सकता।

52. दसवीं अनुमूली के कृष्ण उपर्योगों की व्याख्या इसी के भव्य उपर्योगों को निष्कर्ष करने के लिए नहीं की जा सकती।

53. दसवीं अनुमूली के उपर्योगों का आधारी प्रयोग नहीं किया जाता चाहिए।

#### निष्काशन

54. ग्रानिकादानाओं का दिक्षिकोण यह था कि राजनीतिक दल का नेता दल के सदस्यों को प्राथमिक मददस्यता से निष्काशित कर सकता था और यदि ऐसा किया जाता तो गद्दम विधायिका में भी आगे दल की मददस्यता छोड़ देने।

55. उनका तर्क है कि दल के संविधान के उपर्योगों के अधीन यह निष्काशन किया जा सकता था।

56. उन्होंने स्वीकार किया है कि दसवीं अनुमूली में ऐसा गोई उपर्योग प्रथवा कोई अन्य कानून प्रथवा ऐसे नियम नहीं हैं जिसके प्रधीन वे मददस्यों को निष्काशित कर सकें।

57. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निष्काशित मददस्य, जो विधान मंडल में दल के एक-तिहाई सदस्यों के मामले एक प्रृष्ठ बनाने के लिए मूल दल से अवगत होना चाहने हैं ऐसा ग्रूप नहीं बना सकते।

58. उन्होंने कहा कि प्रथवा को निष्काशित के विषय पर विचार करने का कोई प्राधिकार नहीं है। वह यह सुनिश्चित करने का प्रयाप नहीं कर सकते कि क्या दल के संविधान में सदस्यों के निष्काशन के लिये क्षी गोई प्रतियों का अनुमति दिया गया है प्रथवा नहीं है। किसी उनके ही नियंत्रणों के अनुमार अध्ययन से यह प्रतेकों नों की ही जानी है कि वह उस समस्य-मंडल में जिसे मूल दल से विधान मंडल में उस दल के कृष्ण मददस्यों की एक-तिहाई संख्या में अवगत होने का प्रधिकार प्राप्त है कृष्ण मददस्यों को न दिने।

59. अनका यह मत था कि यदि ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे अपने दल को मंगठित तथा अपने मददस्यों को अनुशाशित नहीं कर सकते।

60. उनका विचार था कि दल के मददस्यों तथा मपथ रूप से उनके दल के बीच एक संविधान दायित्व है तथा इस विषय पर न्यायालय अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिनिर्णय नहीं किया जा सकता।

61. उनका यह तर्क था कि किसी दल तथा उस दल के सदस्यों के बीच का संबंध उसी प्रूषाग का है जैसा कि किस फलब तथा उस सम्बन्ध के मददस्यों के बीच होता है।

62. ग्रानिकादानाओं ने इस मुद्रे पर उपर्युक्त ढंग में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

63. इस मंदर्भ में पैरा 2(1) का संगत है:

"(क) मतन को किसी निर्वाचित मददस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का यदि कोई ही सदस्य है जिसने इसे ऐसे मददस्य के रूप में निर्वाचित के लिए प्रभार्यों के रूप में छोड़ा किया था;

मददस्य को यह संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया है जिसे उसके निष्काशन के बाद भी नहीं छोड़ा जा सकता।

64. विधान मंडल का कोई सदस्य मतन में केवल इस आधार पर ही नहीं आ जाता है कि उसके बल ने उसे चुनाव के लिए टिकट दे दिया बल्कि इस कारण से भी आता है कि मतदाताओं ने उसे चुना है वह भेदवल अपने दल के प्रति ही उत्तरदायी नहीं है बरन् मतदाताओं के प्रति भी उत्तरदायी होता है।

65. यदि यह किसी प्रकार का अनुबंध है तो यह अनुबंध दो दलों के बीच नहीं है बरन् यह विपक्षीय अनुबंध है। यह अनुबंध मददस्य उसके दल आर अनन्दलालों के बीच होता है। मतदाताओं के प्रति उनका वाचित, दल के प्रति उसके दायित्व से कहीं प्रधिक होता है।

66. अपने दल का मददस्य होने के नामे उसके अधिकार और दायित्व उसके दल के संविधान में जड़े उद्भूत होते हैं। तब दलगत मासनों के प्रयोजनार्थ वह दल के संविधान से बंधा होता है।

67. विक्षण मंदर्भ के मददस्य के रूप में उसके अधिकार और दायित्व भारत के संविधान और अन्य मंगल विधियों/नियमों से उत्पन्न होते हैं। अपने गंभीर अधिकारों और कर्तव्यों के लिए वह भारत के संविधान द्वारा दसवीं अनुमूली अथवा भारत के संविधान के अन्य भागों अथवा संविधियों और विधानमंडल द्वारा बनाए गए प्रक्रिया नियमों में ऊपर नहीं भाग जा सकता।

68. विधान मंदर्भ का मददस्य होने के नाम भारत के संविधान और अन्य मंगल विधियों के अंतर्गत उसे प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों में उसे दल का संविधान न तो वृद्धि कर सकता है और न ही करती।

69. दसवीं अनुमूली दल-बदल को रोकते और नियन्त्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। जिसका सीधा ममत्य मददस्य की सामिद के रूप में किए गए कार्यों तथा भूल-जूल एवं विधान मंडल में किए गए कार्यों में है न कि विधान मंडल में आहर की उम्मी दलगत नियमितियों में, जो गंभीर नियमितियों से सम्बद्ध नहीं हैं।

70. विभिन्न दल के सेनाओं को अपने दलों को अवधित करने एवं अपने मददस्यों को अनुशाशित करने में मदद करने का प्रधान न तो अधिकार प्राप्त है और न द्वारा उसका कर्तव्य बनता है।

71. कोई विधायक अपने दल के एक मददस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। वह एक विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। दसवीं अनुमूली तब लागू होती है जब वह विधायक के रूप में अपने कर्तव्य पूरे करता है या अधिकारों का इस्तेमाल करता है। दल के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा किए गए कर्तव्यों प्रधान विधायक अधिकारों पर यह लागू नहीं होती है।

72. दल का नेता अपने दल से सदस्य को निष्काशित कर सकता है तथा उसे दल-गत सुविधाओं से भी बंचित कर सकता है। वह सदस्य को दल से बोइंग पद धारण करने में भी बंचित कर सकता है। दल का सदस्य को इन की बैठकों में भाग नहीं में भी मना कर सकता है। दल का नेता मददस्य को इन की बैठकों में भाग नहीं में भी मना कर सकता है। दल का नेता उसे दल के रूप में दल का संविधान अथवा संस्थाओं का मददस्य बनने में भी गोक मना करता है।

73. परन्तु दल का नेता विधायक को ऐसे अधिकारों और संविधाओं से बंचित नहीं कर सकता जो उसे निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नामे आर भारत के संविधान तथा उसकी दसवीं अनुमूली तथा अन्य मंगल नियमों और विधियों के अंतर्गत प्राप्त हैं।

74. दल के संविधान के प्राथमिक अधिकारों और संविधाओं के बारे में उसकी दसवीं अनुमूली के प्राथमिक अधिकारों और उसके अंग के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।

75. भारत का संविधान प्रथवा दसवीं अनुमूली का निर्वाचित दलों के हित में और उसके संविधान के प्रत्यक्ष नहीं किया जाना चाहिए।

76. अध्यक्ष दल के संविधान से बाधित नहीं होता है। उसे तो भारत के संविधान उसकी दसवीं अनुमूली तथा अन्य मंगल नियमों और विधियों के अनुमार अपने कर्तव्यों का वहन करना होता है।

77. योक सभा में 23 दल हैं। उन सभा का आना अन्य-अलग मविधान है। प्रत्येक दल अपने संविधान में जैसे चाहे संगीष्ठन करता भवता सकता है। और हमें संगीष्ठन होने रहते हैं। यह पता लगाना संभव नहीं है कि व्यापक उसमें संशोधन इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुमार किय गए हैं अथवा नहीं।

78. अध्यक्ष द्वारा इनके पालन किए जाने प्रथवा इनमें लंबे दूर होने की अपेक्षा नहीं की जानी। यदि ऐसा किया जाना है तो यह वही उल्लंघनपूर्ण स्थिति होती।

79. अतः यह माना जा सकता है कि चूंकि किसी भवस्य के विद्यायिका के सदस्य के द्वा में संसारीय कार्यकरण के प्रयोगत और उसके ग्राहिकानों और कर्तव्यों के संबंध में और उसके दीर्घ अधिकारों; कर्तव्यों और कार्यकरण के प्रयोगत से भारत के संविधान की दस्तों अनुमती, अथवा भारत के संविधान के किसी अन्य भाग में प्रथमा अथवा किसी संगत कानून में प्रथमा लोक सभा में प्रपनाएँ जाने वाले प्रक्रिया संबंधी नियमों में कोई प्रावधान नहीं है अतः भारत के संविधान और अन्य संगत कानूनों के अंतर्गत मनवालाओं द्वारा किसी विधान मंडल के लिए निर्वाचित किसी सदस्य को निष्कासित नहीं किया जा सकता।

80. यह मानना सही और बैध नहीं है कि यदि किसी दल के किसी सदस्य को दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाय तो, उसकी विधान मंडलीय दल से प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाती है।

81. यह मानना सही और विधि सम्मत नहीं है कि दल के नेता विधायिकों को प्रथमे दलीय संविधान के अन्तर्गत प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करके उसके कानून द्वारा प्रदत्त वायितों और अधिकारों को बदल सकते हैं।

82. विगत में, सदस्यों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निष्कासित किया गया है।

83. विधान मंडल के सदर्यों की दस्तों अनुमूलीय लागू करने के प्रयोगनार्थ केवल उनीं निष्कासित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए विविध दस्तों अनुमूलीय में इस द्वेष्टु प्रावधान द्वारा अन्यथा नहीं।

84. चूंकि निष्कासित की दस्तों अनुमूलीय अथवा किसी अन्य भाग में कोई प्रावधान नहीं है अतः संवदीय प्रयोगत से सदस्यों का निष्कासित विधि सम्मत नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

85. याचिकावालाओं ने कानूनी स्थिति को सही समझा आर उन्होंने कानून भी व्याख्या को स्पीकर किया है।

86. इन्हींलिए उन्होंने इन द्वारा सदस्यों, जिन्हें उसके दावे के मनुसार, निष्कासित किया गया आर वे प्रथमे विधान मंडलीय दलों के सदस्य नहीं ये जिन्हें विशद् याचिकाएँ दावर की हैं। ऐसा करके उन्होंने यह वात स्पीकर की है कि संवदीय प्रयोगनार्थ निर्वाचित विधायिका सदस्यों को उसके दलीय संविधान के अंतर्गत दल के नेताओं द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता।

87. यद्यपि किवित प्रस्तुता से, याचिकावालाओं द्वारा प्रथमे दल के कठित रूप से निष्कासित सदस्यों के विशद् दावर की गई प्रथमी याचिकाओं में इन स्थिति वो नहीं माना गया है।

#### प्रस्तुत

88. विगत में, कलिप्य मामलों में जब सदस्यों को निष्कासित किया गया था, तो उन्हें दल के सदस्यों के साथ साथ निर्वाचित सदस्यों से भ्रष्ट विद्याने के लिए प्रस्तुत कहा जाता था।

89. “प्रस्तुत” शब्द का भारत के संविधान की दस्तों अनुमूलीय अथवा किसी अन्य भाग अथवा किसी अन्य संगत कानून अथवा संसद में प्रपनाएँ जाने वाले प्रक्रिया संबंधी नियमों में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है।

90. किसी दल से सम्बद्ध सदस्य के भारत के संविधान की दस्तों अनुमूलीय के अंतर्गत कलिप्य अधिकार आर वायित होते हैं।

91. इसी कानून के अंतर्गत एक निर्वाचित सदस्य के भी कलिप्य अधिकार और वायित होते हैं।

92. लेकिन ऐसा लगता है कि एक प्रस्तुत सदस्य का कोई विशेष इसी अथवा स्थिति नहीं होती है।

93. इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है और वही उलझी हुई है कि उसके क्या वायित है और उसे क्या अधिकार प्राप्त है।

94. अतः यह मानना सही है कि इन शब्द का कोई निर्गेष कानूनी मर्यादा नहीं है और यह प्रस्तुत प्राप्ति नहीं गए सदस्य के लिए कोई वायित अथवा अधिकार नहीं होता है।

(विधा विधि विधि कद लागू होता है?)

95. (एक) क्या यह निर्गेष लेने की विधि में लागू होता है?

(दो) क्या यह दावर की गई याचिका रो लागू होता है?

(तीन) अथवा यह उस तारीख से लागू होता है जिसको संचेतक का उल्लंघन होता है अथवा इस का विशदा होता है अथवा सदस्य अथवा दल में गामित होते हैं?

96. सामान्य विषय यह है कि बनाय गये कानून भावी प्रभाव से लागू होते हैं।

97. यदि उसे भूतकाली रूप से प्रभावी बनाना हो तो उसका उपबंध विधि में स्पष्ट स्पष्ट से किया जाय।

98. जब विधियों की दो व्याख्याएँ की जा सकती हों—एक उनको भविष्य में प्रभावी बनाने तथा दूसरी उनको भूतकाली रूप से प्रभावी बनाने के लिए तो जो पहली व्याख्या स्वीकार करती होती।

99. विधि की भूतकाली प्रभावी प्रकृति निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। प्रथमः विधियों को भूतकाली रूप से प्रभावी बनाने अथवा उनकी द्वा प्रकार में व्याख्या करने कि वे भूतकाली रूप से प्रभावी बने, गे वजने जा प्रयास करना चाहिए।

100. संविधान की दस्तों अनुमूलीय विधि-प्रभावी है, भूतकाली प्रभावी नहीं।

101. दस्तों अनुमूलीय में उपबंध देने हैं कि उनको भूतकाली रूप से प्रभावी बनाने के लिए उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती अथवा उनके अन्तर्गत लिए गए निर्गेषों को भूतकाली प्रभाव नहीं दिया जा सकता।

102. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रथमे दल के उपबंध के लिए याचिका दी जाती है तो प्रथमे एक सदस्य को निर्वाचित करने का अनुरोध द्वारा उनके समक्ष ऐसी कोई याचिका प्रस्तुत किए विना वे इस संबंध में व्योग्य नहीं कर सकते।

103. दल के नेता द्वारा भलती करने वाले सदस्य को इस संबंध में एक सूक्ष्मा देना चाहिए है कि यहों ने उनके विशद् एक याचिका प्रस्तुत की जाय।

104. यदि एक सदस्य प्रथमे नेता की संमोष्टनक उत्तर देता है तो उस उमाकी गलती को याक कर सकता है तथा इस सामने में भलती करने वाले सदस्य के विशद् कोई याचिका नहीं दी जा सकती।

105. यदि किसी सदस्य को निर्वाचित किया जा सकता है तथा यदि वह एसे सदस्यों के दल में शामिल हो जाता है जो उस सदस्य के लिहर किए जा सकते के तथा की परवाह नहीं करता है तथा सभ्य सदस्य इस विशदा से अपने मूल दल से अत्रांग द्वारा के लिए कवरम उठाने वै कि उनके मूल में आवश्यक सदस्य हैं तथा आदि में उनके सदस्य अपनी सदस्यता द्वा देना है तथा यदि इस गए निर्गेष को भूतकाली रूप से प्रभावी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

106. इन कारणों से यह टीक ही कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की दस्तों अनुमूलीय भूतकाली प्रभावी प्रकृति की नहीं है तथा इसके उपबंधों के अन्तर्गत दिए गए निर्गेषों को भूतकाली रूप से प्रभावी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

107. 11-8-1992 को श्री राम सुन्दर दास तथा तीम अग्न्यों के विद्वा वी गई अपनी याचिकाओं में, याचिकादानाओं ने प्रार्थना की थी कि प्रतिवादियों को निर्झर घोषित किया जाये तथा लोक सभा से उनकी सदस्यता 17-7-1992 से प्रार्थित उम्म तिथि से जब उन्होंने सचेतक के आवाजों का उल्टरंवत किया था, से समाप्त हो गई है।

108. याचिकादाना निर्णय को भूतकाली रूप में लाए करवाना चाहते हैं।

109. प्रथम याचिकाओं में भी यही निवेदन किया गया है।

110. वसवी अनुसूची के अन्तर्गत मधी निर्णय, निर्णय विए जाने को तिथि से नागृ होंगे, भूतनक्षी प्रभाव से नहीं।

क्या अध्यक्ष को संसद में बाहर पार्टी अनिवार्यों तथा उसके नेताओं के निर्णयों के सबध में कोई अधिकार प्राप्त है?

111. दम्भी अनुपमी विद्यायकों द्वारा दस्तवदल को नियंत्रित करने वाया रोकने के लिए है।

112 यह निर्णयों की गपवीय गतिविधियों पर लम्भ होती है।

113. परि कोई विधायक उसको जारी की गई सचेतक के आवेदन का उल्टरोन करता है और स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है, यदि वह कोई नई नई वत्ता तैयार करता है वहाँ यदि वह किसी अध्य पार्टी में शामिल होता है, तो उसे दप्तां अनुपमी के अन्तर्गत दण्डित किया जाता है, उसे अपने विद्याम मण्डन की मदस्यता के लिए निर्झर घोषित किया जाता है।

114. उपरोक्त दण्डित करने के लिए अध्यक्ष, गढ़ सूनिश्चित करने के लिए विद्यायक की जांच करना है कि क्या सचेतक के आवेदन का स्वेच्छा से उल्टरोन किया गया था, क्या सदस्य ने अपना बल छोड़ दिया अथवा वह अन्य दल में शामिल हो गया है, आदि।

115. परि किसी सदस्य को जारी किये भये सचेतक का वह संसद में अपने दल के एन-टिहाई मदस्यों के साथ प्रनुपालन नहीं करता अथवा वह व्यापों ने दीर्घ दल के एन-टिहाई मदस्यों के साथ दल छोड़ता है अथवा गढ़ अंदर में भ्रातो दल के शो-टिहाई मदस्यों के साथ दूसरे दल में शामिल होता है तो दम्भी अनुपमी के पैरा 3 और 4 के अंतर्गत उसे दण्डित नहीं किया जायेगा और विद्याम मण्डन में उसकी सदस्यता निर्झर घोषित नहीं की जायेगी।

116. अध्यक्ष यह निर्णय कर सकता है कि क्या सुप में विधाम मण्डन में विधायक के दल के एक-निहाई अध्यक्ष दो-टिहाई मदस्य हैं और वह यह घोषणा कर सकता है कि उसे निर्झर किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है।

117. उसे यह निर्णय करना होता है कि क्या दल ने डिप्प जारी किया है और क्या इसका स्वैक्षिक रूप से उल्टरोन किया गया है।

118. उसे यह निर्णय करना होता है कि क्या राजनीतिक दल का विभाजन विप्रात मंडन से बाहर रुप्ता है।

119. वह यह निर्णय नहीं कर सकता है कि क्या मूर दल का दावा पैश करने वाले राजनीतिक दल को बहुमत का मर्मवंत प्राप्त है अथवा नहीं।

120. ऐसा निर्वाचन भायोग द्वारा किया जा सकता है।

121. उसके लिये यह आवेदन अधिक नहीं है कि वह संसद के बाहर एक गुट अध्यक्ष दूसरे युट में जाने वाले सदस्यों की विनाश करे।

122. उसके लिये यह पक्ष लाभना आवश्यक नहीं है कि संसद के बाहर किन्तु संसद मदस्य एक गुट में हैं अथवा किन्तु दूसरे में?

123. वह संसद में दल में विभाजन के लक्ष्य का मंजून कर सकता है।

124. लेकिन वह यह कार्य तभी कर सकता है जब वह बाल संसद में किसी सदस्य द्वारा याचिका के माध्यम से उसके व्यापार में लाई गई हो। भी गई है।

125. इन मामलों में, वह स्वतः कार्य नहीं करता। बल क नेता को संसद में अन्ते दल के सदस्यों के कार्यों के द्वारा शामा कहने की अनुमति दी गई है।

126. अध्यक्ष को यह पता लगाना पड़ता है कि क्या भूल संसदीय पार्टी से अलग होने वाले युप में संसद में दल के एक-टिहाई सदस्य हैं अथवा नहीं।

127. उसे यह पता लगाना पड़ता है कि किसी भी अन्य संसदीय दल में शामिल होने वाले युप में संसद में उसके दल के दो-टिहाई गदस्य हैं अथवा नहीं।

128. उसके लिए यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि संसद से बाहर विभाजित होने वाले राजनीतिक दल में संसद में दल के एक-टिहाई सदस्य हैं अथवा नहीं।

129. उसके लिये यह पता लगाना कठिन है कि किस वैचारिक मत-भेदों के कारण दल विभाजित हुआ है।

130. दम्भी अनुसूची कार्यान्वयिता करने के लिए विभाजन का तर्फ उपरोक्त अधिक संगत है।

131. अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार संसद में सांसदों की गतिविधियों के संबंध में अधिक मुख्य है।

132. संसद के बाहर सांसदों की कार्यवाहियों के संबंध में यह प्रभावी नहीं है।

133. दम्भी अनुसूची का मस्तव्य राजनीतिक दलों और उनके मदस्यों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना मार्ग निर्देश करता और निर्देश देता तथा संसद से बाहर संसद मदस्यों की भूतों-जूतों के लिए उन्हें दण्डित करना नहीं है।

134. अध्यक्ष से यह आशा नहीं की जाती है कि वह राजनीतिक दलों को कमज़ोर अथवा भजवत रखने में अथवा संसद सदस्यों को भ्रातों विभाजन के लिए अनुशंसित रखने में हत्यकाम करे।

135. संसद से बाहर सम्बद्ध सदस्यों से संबंधित दलगत मामलों में अन्य मंडों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिनकी अध्यक्षता अन्य प्राधिकारी करते हैं, न कि अध्यक्ष।

कारण जिन पर निर्णय आधारित हैं

दस्तावेज—झी-1

136. दिनांक 7-8-1992 को लोक सभा के 20 सदस्यों द्वारा भेजे गए आवेदन में सदन में उनके बीठने के लिए अलग स्थानों की मांग को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत भेजा गया आवेदन नहीं माना जा सकता।

137. इसे अधिक से अधिक साक्ष भाना जा सकता है जिसे दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दायर याचिकाओं में प्रयोग में लाया जा सकता था।

138. वास्तव में अपेक्षित संस्था में सदस्यों द्वारा संसद के बाहर और संसद के अंदर किसी राजनीतिक दल के विभाजन को अध्यक्ष से यह उद्घोषणा प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि दल का विभाजन उचित और बैध है।

139. दल को विभाजित करने वाले सदस्यों के विरुद्ध दायर याचिका में इसी तथ्य को यह दिखाने के लिए बचाव के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है कि उक्त संसदीय दल से पृथक होने वाले भूमूह में दल के एक-सिहार्द रास्ता है।

140. लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 4 के अंतर्गत ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है जो इस प्रकार है:

"4. सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जोकि अध्यक्ष निर्वाचित करें।"

141. जिस दिन अर्थात् 7-8-1992 को आवेदन पत्र दिया गया था, दस्तावेज के सभी हस्ताक्षरकर्ता उस दिन जनता दल संसदीय दल के निर्वाचित सदस्य थे।

142. यह तर्फ स्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्री अजित सिह तथा तीन अन्य सांसदों और चार अन्य सांसदों को भी पार्टी अध्यक्ष द्वारा दल की प्राथमिक सदस्यता से आवेदन पत्र देने अर्थात् 7-8-1992 से पूर्व निर्वाचित कर दिया गया था, ये मंसद में जनता दल के संसदीय दल के सदस्य नहीं थे और वे जनता दल के संसदीय दल से अलग हो रहे दल के वैध सदस्य नहीं थे।

143. संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों को निरस्त करने के लिए सांसदों को उनके दल के नेताओं द्वारा संसदीय दल की सदस्यता समाप्त करने के लिए उनकी दल की प्राथमिक सदस्यता वैधानिक और वैध रूप से समाप्त की जा सकती है।

144. विधान में ऐसे उपबंध नहीं हैं जो मंसद सदस्यों के उस प्रकार के निष्कासन की अनुमति देते हैं।

145. दल के संविधान के अंतर्गत मंसदीय दल की सदस्यता समाप्त करने के लिए दल की उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर देना वैध और स्वीकार्य नहीं है।

146. यदि ऐसा करने दिया जाये तो दसवीं अनुसूची के उपबंधों का प्रयोगन ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा किसी दल के संविधान से, जो कभी भी बदला जा सकता है, कुछ थातें देश के भौलिक कानून में शामिल करने के समान होगा।

147. निर्णय के अन्य भागों में दिये गए कारणों से यह निर्णय दिया जाता है कि सर्वश्री अजित सिह, रशीद मसूद, दूरपाल पंवार, सत्यपाल सिह यादव, राजनाथ सोनकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अब्दुल और शिव शरण वर्मा संगत तारीख अर्थात् 7-8-1992 को जनता दल के मंसद सदस्य थे।

148. उक्त तारीख को अर्थात् 7-8-1992 को यह घोषणा करने के लिए वे अहंता प्राप्त नहीं थे और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, उनके विरुद्ध याचिकाएं दायर नहीं की गई थीं।

149. विरोधी पक्ष द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के लिखित में उत्तर यह बताया गया है कि श्री राम सुन्दर

दास और तीन अन्य सांसदों ने सरकार के विरुद्ध रखे गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए उन्हें दिये गए निर्देशों का उल्लंघन किया इसलिए इन चारों सांसदों को 17-7-1992 से लोक सभा की सदस्यता के लिए निहैर पाया गया। अतः वैध रूप से ग्रूप का दर्जा दिलाने के लिए इस सदस्यों की संख्या को उसने नहीं जोड़ा जा सकता।

150. 7-8-1992 को कोई याचिका नहीं दी गई थी और न ही कोई ऐसी याचिका उनके विरुद्ध लबित थी जिसमें यह शिकायत की गई हो कि उन्होंने सचेतक के आदेशों का उल्लंघन किया है वे उन्हें लोक सभा की सदस्यता से अग्रोग्य घोषित किया जाये।

151. 7-8-1992 को वे लांक सभा के वर्तमान वैध सदस्य थे और वे जनता दल में शामिल थे।

152. निर्णय के अन्य भागों में यह माना गया कि इन मामलों में दिये गये निर्णयों को पूर्वप्रभावी या भूलक्षणीय रूप से सदस्य हो सकते हैं जो कि मूल दल से अलग होने की मांग कर रहे हैं।

153. अतः यह माना जा सकता है कि वे उस दल के वैधानिक रूप से सदस्य हो सकते हैं जो कि मूल दल से अलग होने की मांग कर रहे हैं।

154. 22-8-1992 को अग्रोग्य घोषित किये जाने हेतु सर्वश्री श्री राम शरण यादव, अमय प्रताप सिह, रामलखन सिह यादव, अनादि चरणदास, रोशनलाल, अर्जन सिह यादव, उपेन्द्रनाथ वर्मा तथा सूर्य नारायण यादव के विरुद्ध याचिका दी गई थी।

155. तथापि, संबंधित तिथि अर्थात् 7-8-1992 को उनके विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं थी।

156. संबंधित तिथि को वे जनता दल के मंसदीय दल के मौजूदा सदस्य थे।

157. संबंधित तिथि अर्थात् 7-8-1992 को आवेदन पर सभी हस्ताक्षरकर्ता संसद में जनता दल के वर्तमान सदस्य थे।

158. उनकी संख्या 20 के बराबर थी जो कि संबंधित तिथि को लोक सभा में जनता दल के कुल 59 सदस्यों की संख्या के एक तिक्ष्णार्थ से अधिक है।

159. इस प्रकार आवेदन पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह आशय व्यक्त कर दिया या कि मंसद के बाहर जनता दल का विभाजन हुआ है।

160. इस प्रकार आवेदन पत्र से यह पता चलता है कि लोक सभा में जनता दल के मंसदीय दल का विभाजन हुआ है।

161. तथापि इस निश्चिन घोषणा के प्रभावों को शिथिन तथा कुछ सुबोध बना दिया गया था सभी तथां तथा दोनों दलों के बाद में तकों के बाद जो निश्चिन घोषणाएं की थीं वे इस बात को इंगित करती हैं कि जनता दल का बाहर तथा संसद के भीतर विभाजन हो गया है जो कि कमालः पहले तथा संबंधित तिथि को हुआ था।

162. अतः उनके इस अनुरोध के आवेदन पत्र को फि उन्हे अलग से बैठने दिया जाए, अनुमति दी जाती है तथा दी गई।

श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य के विशद् विषयों के उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाएं

श्री राम सुन्दर दास के विशद् याचिका

163. याचिकादाता द्वारा याचिका में दिये गये अधिकांश प्रकथनों का खण्डन नहीं किया गया है और वे प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किये गये हैं।

164. प्रत्यर्थी द्वारा मतदान से प्रविरत रहने के मामले पर ही केवल भिन्न वृष्टिकोण अपनाया गया है।

165. याचिकादाता का प्रकथन है कि प्रत्यर्थी ने जान बूझकर छिप का उल्लंघन किया है। प्रत्यर्थी जोर देकर कह रहा है कि वह मतदान से जानबूझ प्रविरत नहीं हुआ।

166. प्रत्यर्थी का कहना है कि 17-7-1992 को उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसका ब्लड प्रैशर घट-वड़ रक्षा था और दोपहर बाद वह लाइब्रेरी में आराम कर रहा था।

167. उसके अनुसार जब मतदान के लिए धंटी बजी सो उसने लोक सभा चैम्बर में जल्दी-जल्दी आने की कोशिश की किन्तु अस्वस्थता तथा टांग में चोट के कारण वह दरखाजा बंद होने से पहले वहाँ नहीं पहुंच सका और इस प्रकार वह सदन में प्रवेश नहीं पा सका तथा पूरी तरह से चाहते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत नहीं दे सका।

168. प्रत्यर्थी ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए ही स्वयं की परीक्षा की।

169. उसने अपने वृष्टिकोण से सम्बन्धित किसी भी अन्य बात पर किसी प्रकार का कोई अन्य साक्ष्य दर्ज नहीं कराया।

170. लाइब्रेरी और लोक सभा चैम्बर के बीच का रास्ता धीरे-धीरे चलने वाला व्यक्ति भी बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है वशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति जान बूझकर महुत धीमा अलना आरम्भ न कर दे या केन्द्रीय कक्ष में बैठे लोगों से या रास्ते में मिलने वाले लोगों से बातचीत में व्यस्त होकर रास्ता पार करने की परवाह ही न करे।

171. लाइब्रेरी में जिस ढंग से आराम किया जा सकता था वैसा आराम प्रत्यर्थी लोक सभा में कर सकता था क्योंकि लाइब्रेरी आराम करने की जगह नहीं है और वस्तुतः वहाँ सही ढंग से आराम करने की सुविधाएं भी नहीं हैं।

172. प्रत्यर्थी को उस आकस्मिकता को समझ लेना चाहिए था जिसमें वह अब स्वयं को पा रहा है और उसे प्रस्ताव पर मतदान के लिए सदन में रहना चाहिए था।

173. उसके द्वारा दिया गया तर्क विश्वासजनक और स्वीकार्य महीं है।

174. अतः यह निकर्प निकाला जाता है कि प्रत्यर्थी का मतदान से प्रविरत रहना अस्वैच्छिक नहीं था।

175. प्रत्यर्थी भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के प्रावधानों के अनुरूप अनर्हता का दायी हो गया है और इसलिए निर्णय की तारीख से लोक सभा का सदस्य नहीं रहा।

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा के विशद् याचिका

176. इस याचिका में एक मात्र विवादग्रस्त बात भी 17-7-1992 को सरकार के विशद् अविश्वास प्रस्ताव पर प्रत्यर्थी द्वारा मतदान में प्रविरत रहने से संवंधित है।

177. प्रत्यर्थी के अनुसार, वह प्रस्ताव पर मत देना चाहता था तथा उक्त तिथि को सबैरे संसद भवन में था।

178. सायंकाल में उसने सविकल र्बोग्डिलाइटिस तथा कुछ अन्य कारणों से अपने आपको अस्वस्थ महसूस किया, इसलिए दवा लेने तथा आराम करने के लिए अपने घर चला गया।

179. अपने घर पर उसने कोई जड़ी खूटी थाली दवा भी जिससे वह बेहोश हो गया, इसलिए वह संसद भवन जाकर प्रस्ताव पर मत नहीं दे सका।

180. उसका कहना है कि उसने पार्टी के नेता को यह सूचित भी कर दिया था कि यदि उसके लिए सभा में उपस्थित रहना आवश्यक हो, तो उसे डाक्टर की सहमति से एम्बुलेंस में लोक सभा ले जाया जा सकता है। लेकिन उस बारे में कुछ नहीं किया गया।

181. प्रत्यर्थी ने अपने वृष्टिकोण के समर्थन में अपनी तथा अन्य साक्षियों की परीक्षा की। याचिकादाता के बकील द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा की गई।

182. उसने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया।

183. प्रत्यर्थी का वृष्टिकोण विश्वासजनक तथा स्वीकार्य नहीं है।

184. उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य विरोधात्मक है तथा स्वीकार्य नहीं है।

185. उसके साथी द्वारा दिया गया साक्ष्य भी विश्वासजनक तथा स्वीकार्य नहीं है।

186. उसके दस्तावेजी तथा मौलिक साक्ष्य में विरोधाभास है।

187. उसके द्वारा तथा उसके साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य में विरोधाभास है।

188. जिस दृष्टिसे वह पीड़ित थे, वह ऐसी नहीं थे कि वह मत देने के लिए सोकसेभा के चैम्बर में न ज

189. यदि वह बास्तव में मत देना चाहते थे तो वह ठीक भतवान के समय लोक सभा में आ सकते थे और उसके बाद आराम के लिए अपने घर या विशिष्टीय गहायना के लिए डाक्टर के पास जा सकते थे।

190. उमका यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि उसने अपने दल के नेता से कहा था कि यदि सभा में उसकी उपस्थिति अत्यावश्यक हो तो डाक्टर की अनुमति भे उसे किसी बाहन में सभा में ले जाया जाये। वह अपने नेता से यह न कहकर कि वह उसे वहां ले जाये, स्वयं लोक सभा के बैंबर में जा सकते थे। उसके द्वारा अपने नेता से यह कहना कि उसे सभा में ले जाये, अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति पर डालने का प्रयास प्रतीत होता है।

191. सभा के एक जिम्मेदार सदस्य के स्पष्ट में वह सभा में उपस्थित रहकर मत दे सकते थे।

192. यह तथ्य कि वह उससे अगले ही दिन उड़ीसा अपने गांधी खले गए, इस बात को प्रकट करता है कि वह सम्बद्ध तिथि को बहुत खराब हालत में नहीं थे।

193. यह तर्क कि उसने आवश्यकता पड़ने पर अपने पार्टी के नेता से उसे सभा में ले जाने के लिए कह दिया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी दूसरे सदस्य से परामर्श करके गढ़ा।

194. साक्षी के तौर तरीके से लगता है कि वे बनावटी ध्यान दे रहे थे।

195. अविश्वासजनक अभिवाकों, जिए गए साक्ष्य तथा तर्कों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि प्रत्यर्थी ने अपने व्यक्ति से बाहर की परिस्थितियों के कारण अस्वेच्छा से मत नहीं दिया।

196. अतः यह निर्णय दिया जाता है कि वह स्वेच्छा से मतदान से प्रवर्तित रहे तथा वह इस निर्णय की तारीख से लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरहूं होने के बायी हो गए हैं।

श्री गुलाम मोहम्मद खां के विरुद्ध याचिका

197. इस याचिका में भी विवाद का मुद्दा अन्य तीन मामलों में विवाद के मुद्दे के समरूप है।

198. प्रत्यर्थी का अभिवचन है कि 17-7-1992 को वह अस्वय था तथा मधुमेह एवं अन्य ध्याधियों से पीड़ित होने के कारण राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भरती था।

199. उनका कहना है कि उन्होंने अपने दल के नेता को सूचित कर दिया था कि यदि उसकी उपस्थिति सदन में आवश्यक हो तो डाक्टर की सहमति से उन्हें वहां ले जाया जाना चाहिए।

200. उनका कहना है कि वह प्रस्ताव पर मतदान करने के इच्छुक थे परन्तु परिस्थितियों के उसके नियंत्रण से बाहर होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके।

201. अपना दृष्टिकोण मिछ करते के लिए उन्होंने स्वयं की एवं अन्य दो माक्षियों की परीक्षा की। प्रत्यर्थी के बीच द्वारा उनकी एवं अन्य माक्षियों की प्रतिवरीका की गई।

202. अपने अभिवचन के समर्थन में उन्होंने कनिष्ठ दस्तावेजों को प्रस्तुत किया।

203. 17-7-1992 को वह अपने घर बापस आ गए। इस तथ्य से इस धारणा वी पुष्ट होती है कि 17-7-1992 को उनका स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं था।

204. उनका यह दृष्टिकोण कि दल के नेता को डाक्टर वी सहमति से उन्हें सदन में ले जाना चाहिए, अन्य याचिका के प्रत्यर्थी श्री गोविन्द चन्द्र मृदा के दृष्टिकोण के समान हैं।

205. यह विश्वासजनक एवं स्वीकार्य नहीं है। जो कुछ वह अपने नेता से करते को कह रहे हैं, वह तथ्य भी कर सकते थे।

206. वह अपने ऊपर भे किसी अन्य पर जवाबदेही उनके के प्रयास का एक भाग प्रतीत होता है।

207. सदन के एक जिम्मेदार सदस्य के नामे उन्हें मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए था।

208. चूंकि वह नई दिल्ली में ही थे इसलिए भदन में मनदान मंबधी अपने दायित्वों का निर्वहन करना उनके लिए कठिन नहीं होता चाहिए था।

209. उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वासजनक नहीं है।

210. अन्य साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य भी अधिक विश्वास पैदा नहीं करता। उनका व्यवहार गंभीर एवं विश्वासजनक प्रतीत नहीं होता।

211. उनके मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कठिपय विरोधाभास है।

212. उनके तथा उनके साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य में कठिपय विरोधाभास है।

213. इन तथ्यों के परिशेष में प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया यह अभिकथन कि मतदान से उनकी प्रविरति अस्वेच्छिक थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

214. अतएव, यह निर्णय दिया जाता है कि वह इस निर्णय की तारीख से संसद सदस्य के रूप में निरहूं हो गए हैं।

श्री राम सदन के विरुद्ध याचिका

215. प्रत्यर्थी का अभिकथन है कि 17-7-1992 को वह लोक सभा में उपस्थित था तथा उसने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान का बटन दबाया था परन्तु मरीन में खराबी के कारण उसका मत रिकार्ड नहीं हो सका।

216. उनका कहना है कि उन्होंने मदन में उपस्थित अटेंडेंट में पूछा था कि वह बोर्ड पर उनका मत रिकार्ड हुआ है अथवा नहीं। उनके कथनानुसार, अटेंडेंट ने उन्हें सूचित किया था कि उनका मत रिकार्ड हो गया है।

217. उनका कहना है कि उनकी दृष्टि बमजोर है और इसलिए वे बोर्ड को देखकर ठीक प्रबार यह पता नहीं लगा पाये कि उनका मत वस्तुत रिकार्ड हुआ है अथवा नहीं।

218. उनका अभिकथन है कि वह अपना भत देना चाहते हैं ये परन्तु घटनावश वह अपना मत नहीं दे सके।

219. अपने अभिकथन के समर्थन में उन्होंने म्याप की परीक्षा की।

220. उन्होंने अपने अभिकथन की सम्पुष्टि में सदन के अटेंडेंट को अपने साक्षी वे रूप में परीक्षा नहीं की।

221. प्रत्यर्थी का अभिकथन विज्ञामनक तथा स्वीकार्य नहीं है।

222. उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया साध्य विष्णामनक नहीं है।

223. और इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सभव नहीं है कि मतदान में उनकी प्रविरति ग्रस्तैच्छिक थी।

224. अतएव यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रन्थी ने हम निर्णय की तारीख से लोक सभा का सदस्य होने की निरहंता का दायित्व अपगत किया है।

श्री रामशरण यादव तथा सात अन्य के विरुद्ध याचिकाएँ आठ याचिकाएँ।

225. 22-8-1992 को श्री वी.पी.सिंह न सर्वश्री राम शरण यादव, अभय प्रताप सिंह, राम लखन सिंह, यादव अनादि चरण दास, रोशन लाल, अर्जेन मिह यादव, उपेन्द्र नाथ बर्मा तथा सूर्य नारायण यादव, मधी लोक सभा के सदस्य, के विरुद्ध भारत के सविवान की दमकी अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत याचिकाएँ दायर की।

226. मधी याचिकाओं की विषय वस्तु एक जैसी है। इसलिए उन पर एक साथ विचार किया गया है।

227. सारस्य में याचिकादाता का दृष्टिकोण निम्नवत है।

(एक) प्रत्यर्थी ने यह दावा नहीं किया कि जनता दल राजनीतिक पार्टी में 7-8-1992 में पूर्व विभाजन हुआ तथा यह कि वह किमी एक गूढ़ से सम्बन्धित है।

(दो) दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) में सदसद में दल के विभाजन से पूर्व राजनीतिक दल में विभाजन की स्फूर्ति की गई है, जो कि हुआ नहीं दिखाया गया है।

(तीन) श्री अजित सिंह नथा मान अन्य सासदों को मगन तारीख, अर्थात् 7-8-1992 में पूर्व तीन तारीखों को इन की प्राविमिक सदस्यता गे निवन्धित किया गया। प्राप्त ग्रांति विवरण की तारीखों को वे सदसद में जनता दल के सदस्य नहीं रह गए थे।

(चार) श्री राम सुन्दरदाता तथा तीन अन्य सासदों ने 17-7-1992 को जारी किए गए विष्य का उल्लंघन किया था। अतएव वे विष्य का उल्लंघन करने की तारीख गे लोक सभा की सदस्यता से निरहंत होने के दायी हो गए थे।

(पांच) इस प्रकार प्रत्यर्थी मदसद में जनता दल के 1/3 सदस्यों का समूह नहीं बना सके क्योंकि निवन्धित सदस्य तथा निर्गत मदस्य 7-8-1992 को समूह का भाग नहीं बन सकते थे।

(छह) इन कारणों से, प्रत्यर्थियों ने 7-8-1992 दो लोक सभा के सदस्य होने की निरहंता का दायित्व अपगत किया है।

(मात्र) तीन समूह-ग्राम निष्कासित सदस्यों का समूह, दूसरा उन सदस्यों का समूह, जिनको छिप के उल्लंघन के कारण मदसद की सदस्यता छिप गई तथा उन प्रन्थियों का समूह, जो भारत के सविवान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) के अन्तर्गत नाम का दावा करते होने के लिए समूह बनाने के लिए इकट्ठे नहा हो सके।

(आठ) याचिकादाता के अनुसार, जिन सदस्यों को इन के गवाह द्वारा दल की प्राविकारा मदस्यता में निष्कासित कर दिया गया था, उनकी समस्याएँ दल की मदस्यता निष्कासन की तिथि में समाप्त हो गई।

(नौ) भूतपूर्व अध्यक्षों ने उपरोक्त स्थिति को स्वीकार किया था उन्होंने निष्कासित सदस्यों को अमम्बद्ध सदस्य माना था।

(दस) जनता दल के अध्यक्ष ने समद में अपने दल के सदस्यों को दल विशेष गतिविधियों के कारण ग्रस्त अलग अलग तारीखों को निष्कासित किया और निष्कासन की छन तारीखों में अनेक दिनों का अवरान है।

(म्यारह) अन्य राजस्य समद में जनता दल के सदस्य बने रहे। वास्तव में कुछ ने दल के भूतावों में भी भाग लिया।

(यारह) प्रत्यर्थियों का कहना है कि जनता दल के अध्यक्ष द्वारा आठ सदस्यों को निष्पासित करने के पहले अध्यया उसके बाद जनता दल राजनीतिक पार्टी का कोई विभाजन नहीं हुआ।

(तेरह) उनका कहना कि दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) के अंतर्गत उन्मुक्ति का दावा करने के लिए राजनीतिक दल में विभाजन होता चाहिए और बाद में संसदीय दल में भी विभाजन होता चाहिए। दो विभाजनों के बिना सदस्य दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) के अंतर्गत उन्मुक्ति का लाभ नहीं उठा सकते।

(चौथह) उनका कहना है कि श्री अर्जित सिंह ने अदालत और निवाचित आयोग के समक्ष अपने अभिकथनों में राजनीतिक दल में विभाजन का दावा नहीं किया है तबका कहना था कि वह मूल जनता दल के अध्यक्ष थे।

(पन्द्रह) दल-बदल विरोधी कानून में व्यवस्था है कि एक राजनीतिक दल और एक विधात दल होगा।

(सोलह) संसद के कुछ सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल में विभाजन नहीं किया जा सकता। विभाजन बड़ी मंज्या में दल के मदस्यों द्वारा ही हो सकता है।

(सत्रह) अतः यह माना जा सकता कि जनता दल राजनीतिक पार्टी में कानून के अनुसार विभाजन हुआ।

(अठारह) अध्यक्ष को 7-8-92 को संसद में ग्रलग मीटिंग निर्धारित करने के लिए आवेदन करने में प्रत्यर्थियों का आचरण दल छोड़ने की कोटि में आता है जैसाकि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(29) के अन्तर्गत अनुधात है।

(उन्नीस) याचिकादाता ने प्रार्थना की है कि यह घोषित किया जाए कि प्रत्यर्थी निरहस्ता के अध्यधीन हो गए हैं और वह 7-8-92 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।

228. प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित कथन 31-8-92 को दायर किए।

इसमें सारलेप में यह कहा गया है कि—

(i) याचिकादाता द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अन्य भागों में वर्ण अभिकथनों में दिया है।

(ii) प्रत्यर्थियों का दावा है कि वह मूल जनता दल के सदस्य हैं और उनका यह दावा अन्य मंत्रों पर सिद्ध होगा।

(iii) उनका कहना है कि 7-8-1992 को संसदीय दल का विभाजन हुआ और जो दल अन्य हुआ वह जनता दल नंसदीय पार्टी के एक-तिहाई मदस्यों के बाबाबर है।

229. इस मामले में याचिकादाताओं द्वारा किए गए दावे और अर्जित सिंह और श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सांसदों के विरुद्ध शायर किए गए दावे और इन याचिकादातों में और अन्य याचिकादातों में प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए दावे भ्रम में डालने वाले और परस्पर विरोधी हैं।

230. दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावे में विद्यमान अंतर्कारोध के बाबजूद अभिकथनों, साक्ष्यों, और तकी के सारणित होने के कारण जनता दल 7-8-1992 में पहले विभाजित हो गया। इन दोनों दलों ने न्यायालय तथा निवाचित आयोग के समक्ष भी जो तिवेदन किए हैं वे भी पर्याप्त सारणित हैं। इसलिए दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) में जिन उन्मुक्ति के लिए उपबंध किया गया है उसके लिए प्रत्यर्थी दावा कर सकता है।

231. यह पहले अभिनिर्धारित है कि जनता दल का अध्यक्ष मंसदीय दल के श्री अर्जित सिंह तथा अन्य तीन सदस्यों को निष्पासित नहीं कर सकता और उसके अधिकारों और कर्तव्य को न्यून भी नहीं कर सकता। वे जनता दल के संसदीय दल के मदस्य बने रहेंगे।

232. यह भी अभिनिर्धारित है कि 7-8-1992 को श्री राम सुन्दर दाम तथा अन्य तीन सदस्य जनता-दल के संसदीय दल और लोक सभा के विद्यमान सदस्य थे। अतः वे उस नारीख को जनता दल के संसदीय दल के पृथक ग्रुप का एक भाग गठित कर सकते थे।

233. अतः यह अभिनिर्धारित करना कठिन नहीं है कि श्री अर्जित सिंह और सात अन्य सांसद, श्री राम सुन्दर दाम और अन्य तीन सांसद तथा प्रत्यर्थी संसद में जनता दल के एक-तिहाई सदस्यों से युक्त ग्रुप को गठित कर सकते थे तथा जनता दल संसदीय दल के अन्य सदस्यों से पृथक हो सकते थे और इसके लिए उन्हें निरहु नहीं माना जा सकता।

234. याचिकादाता का यह तर्क विधिमाल्य, वैध और उचित नहीं है कि दल से निष्पासित सदस्यों की संसदीय दल की सदस्यता समाप्त हो गई है। इसे अनुचित मानने के कारणों के बारे में पूर्ववर्ती पैराओं में बताया गया है।

235. विगत में “असम्बद्ध” शब्द के अर्थ को जिस रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बारे में भी पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लेख किया गया है। इस मामले में याचिकादाता द्वारा दिए गए सुझाव उचित और विधिमाल्य नहीं है।

236. इसीलिए यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के संदर्भ में प्रत्यर्थी लोक सभा की सदस्यता के लिए निरहु संवित हुआ है।

237. अतः इस याचिका को खारिज किया जाता है।

श्री अर्जित मिह तथा अन्य तीन के विषद् निम्न  
2(1) (क) के अधीन याचिका ।

श्री अर्जित मिह तथा अन्य तीन के विषद् याचिका

238. जनता दल संसदीय दल के मुख्य सचेतक श्री श्रीकांत जैना ने 3-10-1992 को भारत के विधायन की दम्भी अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के सदम् में सर्वधी अर्जित मिह, रणीद मसूद, हरपाल पंवार तथा सदापाल मिह यादव के विषद् मंग्रुक्त याचिका फाइल की थी ।

239. यह याचिका जनता दल संसदीय दल के नेता श्री श्रीविनाथ प्रताप मिह द्वारा फाइल नहीं की गयी थी ।

240. याचिकादाना इस बात को दुहराना है कि प्रत्यर्थी ने २३ के अध्यक्ष द्वारा जनता को प्राथमिक सदस्यता में निष्कामित किया गया था, अन्य चार सदस्यों को भी उन्होंने दल-विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कामित किया गया था, तथा अन्य चार इस प्राधार पर भी लोक सभा की सदस्यता किए निर्ण साक्षित होते हैं कि उन्होंने मनेतक के आदेशों का उन्नंघन किया है ।

241. याचिकादाना का कहना है कि 7-8-1992 को प्रत्यर्थियों और चार अन्य निष्कामित सदस्यों तथा अन्य चार सदस्यों, जो निरर्झणीय हो गये थे तथा अन्य आठ सदस्यों ने लोक सभा में अपने लिए पृथक् स्थान की मांग करते हुए एक आवेदन किया ।

242. उमका कहना है कि श्री अर्जित सिंह ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दावा किया था कि 5-2-1992 को जनता दल का विभाजन हो गया था और उन्हें मूल जनता दल का अध्यक्ष बनाया गया था ।

243. याचिका का पैरा 7 बहुत ही प्रासंगिक है और उमका पाठ निम्नप्रकार है :

“कि किसी संसद सदस्य के उमकी अपनी पार्टी द्वारा निष्कामित से सभा में उसकी सदस्यता ममाप्त नहीं हो जाती इयोंकि दम्भी अनुसूची के पैरा 2(1)(ग) का, जिसे ममीदा विधान में मूलरूप से शामिल किया गया था, संशोधन विधेयक मेंलोप कर दिया गया था । इसलिए याचिकादाना ने उसके विषद् निष्कामित आदेश जारी किये जाने का तुरन्त बाद सभा से प्रत्यर्थियों की निरहंता की मांग करते हुए उनके विषद् याचिका दायर नहीं थी ।

244. याचिकादाना का कहना है कि 5-2-1992 को विभाजन के परिणाम स्वरूप बने धड़े में केवल चार सदस्य थे ।

245. उसके अनुसार, जनता दल संसदीय पार्टी के केवल तीन सदस्यों के साथ जनता दल के एक धड़े का अध्यक्ष अनन्ते का उनका कृत्य अपनी पार्टी छोड़ने के बराबर था । चूंकि ये चार सदस्य संसद में जनता दल के सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई के बराबर नहीं थे, इसलिए वे 5-2-1992 से लोक सभा की सदस्यता से निरर्झणीय हो गये ।

246. याचिका के पैरा 13 का पाठ निम्न प्रकार है : “13 इसलिए प्रत्यर्थियों की उपर्युक्त स्त्रीकृति, जिसके परिणामस्वरूप वे निरहंता के पात्र हो गये हैं, को देखने हुए इस मामले में प्रत्यर्थियों का निष्कामन विधिमाला था अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जाए ।

247. प्रार्थना की जाती है कि प्रत्यर्थियों को 5-2-1992 से लोक सभा के सदस्य बने रहने से निर्गत घोषित किया जाए ।

248. इस याचिका में याचिकादाना का दृष्टिकोण अन्य याचिकाओं में श्री वी.पी. सिंह के दृष्टिकोण से निलकुल मिलता है ।

249. याचिकादाना प्रत्यर्थियों को अपनी याचिका दायर करने की तारीख अर्थात् 3-10-1992 को भी अपनी संसदीय पार्टी के सदस्य के रूप में भानता है और उस दृष्टिकोण का वे परिवर्तन कर देता है जिसके अन्तर्गत उसकी पार्टी प्रत्यर्थियों नया उसकी संसदीय पार्टी के चार अन्य सदस्यों को संमद में अमंबद्ध तथा उसकी पार्टी का न होने के रूप में मानती थी ।

250. यह दृष्टिकोण परस्पर विरोधाभासी है ।

251. प्रत्यर्थियों ने अपना लिखित व्रतान् 4-11-1992 को दिया था ।

252. प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण सारांश : इस प्रकार है :— प्रत्यर्थियों ने आठ सदस्यों के निष्कामन, विषद् के उल्लंघन के आधार पर चार सदस्यों की निरहंता तथा पार्टी छोड़ने के आधार पर आठ सदस्यों की निरहंता के प्रश्नों पर वही बात दोहराई है जो उन्होंने अन्य याचिकाओं में कही थी ।

253. उनका कहना है कि वे मूल जनता दल के सदस्य हैं और इस प्रकार अन्य सभी जनता दल के सदस्य हैं, सिवाए उनके जो विशिष्ट रूप से ऐसा मानते भौद्धार करते हैं ।

254. उन्होंने अन्य अधिकांश बातों का खण्डन किया है ।

255. रिकार्ड में यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि 7-8-1992 से पूर्व जनता दल में विभाजन हो गया था ।

256. दम्भी अनुसूची संसदीय दल में न कि भंसद में बाहर राजनीतिक पार्टी में विभाजन से संबंधित है । यह बानून निर्वाचित सदस्यों में गठित संसदीय पार्टी को संरक्षण प्रदान करता है और भंसद से बाहर राजनीतिक पार्टी को संरक्षण प्रदान नहीं करता । इसका उद्देश्य दल-बदल को रोकना है । इसका उद्देश्य संसद में बाहर राजनीतिक दलों को संरक्षण प्रदान करना नहीं है । इसलिए प्रत्यर्थियों को 5-2-1992 के अपर्याप्त संख्या में पार्टी छोड़ने के आधार पर निर्गत घोषित नहीं किया गया जा सकता ।

257. इसलिए, याचिका खारिज किए जाने लायक है और इसे खारिज किया जाता है ।

वसदीं प्रनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अधीन श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध याचिका।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध याचिका

258. 3-10-1992 को श्री श्रीकान्त जेना, संसद में जनता दल के मुख्य सचेतक ने भारत के संविधान की वसदीं प्रनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अनुसार सर्वे/श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, राम निहोर राय, राम अवध और शिव शरण वर्मा के विरुद्ध एक संयुक्त याचिका दायर की।

259. कुल 14 याचिकाओं में से 12 याचिकाएं संसद में जनता दल के नेता श्री बी०पी० सिंह द्वारा दायर की गई हैं और 2 याचिकाएं संसद में जनता दल के मुख्य सचेतक में श्री कान्त जेना द्वारा दायर की गई हैं।

260. श्री बी०पी० सिंह ने लगभग सभी याचिकाओं में दावा किया है कि श्री अजित सिंह तथा तीन अन्य सदस्यों की दल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई है और इसलिए वे जनता दल संसदीय दल की अपनी सदस्यता खो चुके थे अतः वे श्री बोम्हर्डी की अध्यक्षता वाले जनता दल के एक भाग के रूप में अपेक्षित संघर्ष में सदस्यों सहित अलग घूप नहीं बना सके ताकि अलग होने वाले सदस्य अयोग्य घोषित न हो सकें।

261. श्री श्रीकान्त जेना ने इस याचिका तथा श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई याचिका में दावा किया है कि श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों ने स्पष्ट भावों में स्वीकार किया था कि 5-2-1992 को वे श्री बोम्हर्डी की अध्यक्षता वाले दल से अलग हो गए थे तथा 5-2-1992 को उन्होंने एक नए दल का गठन कर लिया था।

262. यदि नया दल बनाया गया था और यदि श्री अजित सिंह तथा अन्य सदस्य नए दल के सदस्य बन गए थे तो वे अपेक्षित संघर्ष में संसदीय दल से अलग होने के लिए 7-8-1992 को दल में सम्मिलित नहीं हो सकते थे।

263. इस प्रकार 7-8-1992 को अन्य शेष सदस्य केवल 16 थे और वे अपेक्षित संघर्ष वाले घूप का गठन नहीं कर सके और इसलिए इस याचिका में उल्लिखित प्रतिवादी, जिन्होंने 7-8-92 को अध्यक्ष महोदय को दिए गए आवेदन में हस्ताक्षर किए थे, अपर्याप्त संघर्ष में अपना दल छोड़ने के कारण अयोग्य हो गए।

264. श्री बी०पी० सिंह द्वारा कही गई आत श्री कान्त जेना द्वारा कही गई बात के विपरीत है।

265. याचिकादाता ने मांग की है कि प्रतिवादी को एक निश्चित भत आवधि करना चाहिए और उसे कभी स्वीकार और कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए तथापि, याचिकादाता स्वयं उसे कभी स्वीकार और कभी अस्वीकार करते प्रतीत होते हैं।

266. ऐसा प्रतीत होता है कि जनता दल के “ग्राम बोम्हर्डी” के नेतृत्वाधीन गुट ने अपने इस भत को त्याग दिया है कि संसद सदस्यों को संसदीय दल से निकाला जा सकता है।

267. प्रतिवादियों ने 4-11-1992 को अपना लिखित वक्तव्य दर्ज कराया है।

268. लिखित वक्तव्य द्वारा वे कहते हैं कि श्री अजित सिंह और सात अन्य सदस्य कानूनी तौर पर जनता दल उसदीय पार्टी से नहीं निकाले जा सकते थे, कि श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य सदस्य इस आधार पर अनहैं नहीं ठहराये जा सकते थे कि उन्होंने उन्हें जारी किये गये छिप का उल्लंघन किया था।

269. उन्होंने कहा है कि श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्य वास्तविक जनता दल के हैं और इस प्रकार जनता दल संसदीय पार्टी के सभी अन्य सदस्य उसके गुट के हैं वर्तमान में से कोई विशेष रूप से कोई भिन्न घोषणा न करे।

270. ऐसा पहले ही से माना जाता है कि जनता दल के अध्यक्ष श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों को भनता दल की संसदीय पार्टी से निष्काषित नहीं कर सकते थे और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को कम नहीं कर सकते थे। वे जनता दल की संसदीय पार्टी के सदस्य बने रहे।

271. यह भी माना जाता है कि श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य सदस्य 7-8-1992 को जनता दल की संसदीय पार्टी और लोक सभा के बैध सदस्य थे। इसलिए उस तारीख को जनता दल संसदीय पार्टी से अलग हो रहे गुट के सदस्य बन सकते थे।

272. इसलिए ऐसा मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सांसद तथा सोलह अन्य प्रतिवादी संसद में जनता दल के 1/3 सदस्यों का एक गुट बना सकते हैं और अनहैं हुये बिना जनता दल संसदीय पार्टी के अन्य सदस्यों से अलग हो सकते हैं।

273. याचिकादाता का यह भत वैध, कानूनी और उचित नहीं है कि दल से निष्काषित सदस्य संसदीय पार्टी की सदस्यता खो चुके हैं। इसके उचित न होने के कारण पिछले पैरा में दिए गए हैं।

274. इसलिए यह निर्णय लेना संभव नहीं है कि भारत के संविधान की दसदीं प्रनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अनुसार प्रतिवादी लोक सभा के सदस्य रहने के लिए अनहैं हो गए हैं।

275. अतः जब उक्त आवेदन अध्यक्ष को दिया गया, इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य अपेक्षित संघर्ष में उपस्थित थे और इसलिए इस याचिका में जो प्रतिवादी है, वे अपर्याप्त संघर्ष में अपनी पार्टी से अलग हो जाने के आधार पर अनहैं हुये नहीं माने जा सकते।

276. इसलिए यह निर्णय लिया जाता है कि याचिका रद्द किये जाने योग्य है और इसे रद्द किया जाता है।

मामले तथा विधि पर कुछ विचार।

इस प्रकरण में मुझे कितने महत्वपूर्ण जटिल तथा पीड़ा-दायक हैं? इसके नीतिक कानूनी तथा राजनीतिक पहलू।

277. यह मामला महत्वपूर्ण और जटिल है। यह पीड़ा-दायक भी है।

278. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका भारत के लोकन्‌तन्त्र और संसदीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है।

279. यह जटिल है क्योंकि इसमें भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और भारतीय नागरिकों की तथा संसद में उसके प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता, उनके विधिक और दायित्वों की व्याख्या अन्वर्ग स्तर है।

280. दसवीं अनुसूची एक नया कानून है। ऐसे पूर्वोदाहरण अधिक संख्या में उत्तरव्य नहीं हैं जिनके प्राधार पर इसका निर्वाचन किया जाए और इसे नागू लिया जाए। यह म तो सरल है न ही त्रुटिहीन है।

281. इस पूरे मामले में एक आवेदन और चौदह याचिकाएं हैं। याचिकाओं में कुछ तर्क तो परस्पर विरोधी और अप्रासंगिक भी हैं।

282. इस प्रकरण से संबंधित पक्षों से यह प्रवेश गंदी की जाती कि उन्हें इस प्रकरण से जुड़े कानूनी मुद्दों की ठीकठीक जानकारी होगी। उसके दृष्टिकोण कानूनी होने के बजाए राजनीतिक रहे हैं।

283. यह प्रकरण पीड़ादायक रहा है क्योंकि समाज-रामय पर पार्टियों द्वारा ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो आधार पर्हृचाते हैं। किर भी इसे सभी संबंधित पार्टियों द्वारा अन्तःजिम्मेदाराना तरीके से निपटाया गया। इस मामले में उपस्थित होने वाले वकील इस मामले पर प्रकाश डालने में सकूल रहे तथा उन्होंने संयमित और तकनीपूर्ण ढंग से कार्यवाही की चलाया।

284. कुछ व्यक्तियों के अनुसार इस मामले के नैतिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू हैं।

285. नीलगिरि में जुड़े मामलों पर न्याय देना आसान नहीं है। जिन्हें कानून के आधार पर मामलों को निपटाना होता है, उनके लिए मुद्दे पर निर्णय लेते रहय उसमें नैतिकता के सिद्धान्तों को लागू करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पार्टियों द्वारा लिए गए नैतिक निर्णयों और कानूनी निर्णयों के बीच विरोध हो सकते हैं। कानूनन ऐसे मामलों में कानूनी निर्णय को वरीयता मिलती है जिन्हे निर्णय लेना होता है, उन्हें कानून के आधार पर निर्णय लेते सभय भरसक नैतिकता के सिद्धान्त को ध्यान में रखना होता है।

286. इस प्रकार के मामलों में कानून के आधार पर निर्णय लेना होता है। वर्तमान मामले में कानून के आधार पर निर्णय दिया जाना है। कानून के आधार पर निर्णय लेना आसान है। परन्तु यदि कानून स्पष्ट न हो, अथवा उसका सही निर्वाचन नहीं किया जाता है, तो निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है।

287. राजनीतिक मामले और पहलूओं दोनों ही प्रायः स्पष्ट नहीं होते और जटिल होते हैं। वे समस्याओं और मुद्दों को सुनक्षा भी सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और उन्हें जटिल भी बना सकते हैं। वे प्रशंसनीय अथवा अप्रशंसनीय, नरल अथवा पीड़ादायक भी सिद्ध हो सकते हैं।

288. ऐसे मामलों में राजनीतिक पहलूओं के पीड़ादायक विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाले अवसर सीमित भी हो

सकते हैं ग्रंथवा असीमित भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति के बीच अहीं प्राप्त ही कर सकता है कि उनकी भूमिका सीमित और प्रतिष्ठित हो सकती है।

289. वर्तमान मामला 20 सासदों की सदस्यता से संबंधित है जो दो करोड़ से भी अधिक भारतीय नागरिकों के प्रतिनिधि हैं। वे जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। नोकरी में, जनता वा अपना ही महत्व है।

290. तथापि जनता तिनिधियों से यह आपा की जाती है कि वे ज्ञानतों का पालन करेंगे। धर्म-बदल की समस्या पर कावृ पाना आसान कार्य नहीं है। यदि यह समस्या अनियंत्रित रहती है, यह संसदीय और लोकतात्त्विक अवस्थाओं का विनाश कर सकती है।

291. अतः कोई भी कदम अनियंत्रित और आवेगपूर्ण तरीके से नहीं उठाए जाते हैं। बल्कि न्याय करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। जिन्हें कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उन्हें सजा हो सकती है।

292. निर्णय करना आसान नहीं है।

293. जिस व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचना है और निर्णय करना है उसके लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध है कि वह स्वविवेक से न्याय करे। इस मामले में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया गया है।

इस कानून के बारे में कुछ सुझाव

#### दसवीं अनुसूची

294. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को जिन उद्देश्य के लिए साधा गया है वह इसमें काफी हृद तक सफल रही है। इसमें कुछ खामियाँ और दोष भी हैं। उन्हें अब दूर कर दिया गया है और अब वे विन्युल स्पष्ट हो गई हैं। उन्हें अब कानून में नहीं रखा जाना चाहिए।

#### व्याख्याएं

295. इसमें कुछ शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। उनकी उचित व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि उनमें उल्लिखित अवधारणाओं को अधिक सुस्पष्ट और सुध्यकृत बनाया जा सके।

#### संभावित स्थितियाँ

296. विधि जो उत्तरस्थितियों से निपटने का प्रावधान नहीं है जो दल बदल संबंधी मामलों पर विचार करते समय पैदा होती है इसे और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें उन संभव स्थितियों के लिए प्रावधान होना चाहिए जो विधि की व्याख्या करने तथा उने लागू करने में हो सकती है।

#### विधान मंडल के बाहर पार्टी क्रियाकलाप

297. विधान मंडल में दल बदल पर इस विधि के अन्वर्ग कार्यवाही की जाती है। विधान मंडल में दल बदल राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों से संबंधित होती है। संसदीय दलों के सदस्यों के क्रियाकलाप संविधान की दसवीं अनुसूची, अम्ब उपन्धों, अन्य संबंधित विधियों तथा विधान मंडल

द्वारा अनुसरण किये जा रहे कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

298. विधान मंडल के बाहर राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप विधिक उपबंधों के अनुसार नहीं किए जाते हैं क्योंकि इस प्रयोजनार्थ कोई विधि विद्यमान नहीं है। उनको कठिन विधियों के अन्तर्गत रखना सरल अथवा बांछनीय नहीं है। राजनीतिक दलों को अपने क्रियाकलापों को स्वेच्छा से करने की आजानी होनी चाहिए। लेकिन समय-समय पर विधान मंडल में दल बदल पर नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप अपेक्षित ढंग से किए जाएं।

299. इसे कैसे किया जा सकता है इस बात की जान की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों के कुछ क्रियाकलापों को दसवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इसे और अधिक अधिक बनाया जा सकता है ताकि यह अविक प्रभावी बन सके अथवा, सभी संबंधित लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों को अपेक्षित ढंग का बनाने के लिए सहभत होकर कोई अन्य विधान बनाया या पारित किया जा सकता है।

#### निर्णयिक प्रधिकारी

300. इस समय दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामलों पर अध्यक्ष और सभापति निर्णय करते हैं।

301. मृत्ति: उनके निर्णय अन्तिम समझे जाते थे यद्य उन पर न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। विधि में नियमों को अन्तिम गानने और न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा न किये जाने संबंधी उपबन्ध को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि इसका अपेक्षित संबंध में राज्य विधान मण्डलों द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया क्योंकि इसमें न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने की बात निहित है।

302. यदि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिये गये निर्णय को अन्तिम रूप देने के बारे में निर्णय लिया जाता है तो जिस उपबन्ध को रद्द कर दिया गया था उसे इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया द्वारा पुनः बहाल किया जा सकता है।

303. फिर भी न्यायपालिका नियमों की पुनरीक्षा करने संबंधी निहित क्षेत्राधिकार का दबा कर सकती है।

304. परन्तु विधि में अध्यक्ष या सभापति के निर्णय को अन्तिम रूप दिया जाने संबंधी उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत कम और विशेष मामलों में ही किया जा सकता है जोकि बार-बार और नियमित रूप में पुनरीक्षा करने देने के मामलों से भिन्न है।

305. यह विधि में संशोधन करके यह उपबन्ध कर सकते हैं कि यदि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामले संसद से संबंधित हों तो इन मामलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के एक या दो न्यायाधीशों द्वारा और यदि ये मामले राज्य विधानमण्डलों से संबंधित हों तो उच्च न्यायालय के एक या दो न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता है।

306. इन मामलों को निर्णय के लिए न्यायपालिका को देने के अनेक लाभ हैं।

307. कानूनी मामलों को निपटाने के लिए न्यायाधीश नेहरू स्थिर में होते हैं। दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित मामलों पर पूरी तरह से कानून के अनुसार ही निर्णय लिया जाना होता है। अध्यक्ष या सभापति विधि विशेषज्ञ और कानून में गारंगत हो भी सकते हैं और नहीं भी। परन्तु यह निश्चिन है कि वह इस संबंध ने उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य नहीं हो सकते, जिनका मुख्य कार्य ही कानूनी मामलों की सुनवाई करना है और कानून के अनुसार ही उन पर निर्णय देना है।

308. जब दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामलों की अध्यक्ष या सभापति द्वारा सुनवाई की जाती है तो विवाद में संबंधित दल उनके समझ उपस्थित होते हैं और मामलों की पैरवी करते हैं। वे तथ्यों और कानून की व्याख्या की प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों से पूर्णरूपेण अवगत हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए वे इस प्रकार के मामलों पर निर्णय लेने में सीमित रूप से ही सहायक हो सकते हैं।

309. धर्मीय लोग इस तरह से बहस कर सकते हैं और मामलों की पैरवी कर सकते हैं जो मामलों को बेहतर तरीके से निपटाने में सहायता होते हैं, किसी न्यायालय में धर्मीय लोग लोक सभा अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति के सम्मुख पेश हो सकते हैं जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। लेकिन लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के सम्मुख पेश होने की प्रक्रिया और उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सम्मुख पेश होने की प्रक्रिया में अंतर है।

310. जब अध्यक्ष अथवा सभापति के समझ मामले की पैरवी की जाती है तो जो तकनीक दिए जाते हैं उनका आधार कानूनी न होकर राजनीतिक होता है।

311. दसवीं अनुसूची भारत के संविधान का एक अंग है। संविधान की व्याख्या करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। इसलिए यह बेहतर होगा यदि दसवीं अनुसूची से संबंधित मामलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करे।

312. हमारे देश के विधान दलों के पीठसीन अधिकारियों ने इस विषय पर विवार किया है। इस बारे में उनका अपना-अपना दृष्टिकोण है, इन मामलों से वे पुनः विचार करने के बाद निकर्ष निकाल सकते हैं।

313. इस पहलू पर कई अन्य मंचों पर भी विचार किया गया है। इस बारे में अब अंतिम रूप से विचार करके, यथा शोध निर्णय, ले लिया जाना चाहिए।

#### विषय (सचेतक)

314. भारत के सभी नागरिक स्वेच्छा से मतदान कर सकते हैं, लेकिन, जनका के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने दल के नेताओं के निवेशानुसार मतदान करना होता है।

315. इस प्रावधान को विषय का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सम्मिलित किया गया था। दल-बदल विरोधी कानून में इस आधार का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

316. क्या यह आवश्यक है कि जन प्रतिनिधियों को सभी मामलों में एक विशेष ढंग से मत देने के लिए कहा जाए ?

317. सरकार के विशद् अधिकारी विभास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तथा नूनाव घोषणा पत्र में शामिल विषयों पर चर्चा के दीरान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के समस्यों को एक विशेष रूख अपनाने तथा विशेष ढंग से मतदान करने के लिए कहा जा सकता है ।

318. उन सभी विषयों में, जिन पर मत विभाजन के दौरान मत देने के एक विशेष ढंग को अपनाने के निर्देश दिये जा सकते हैं, उसको कानून का एक अंग बनाया जा सकता है तथा उसका सभी दलों और सदस्यों द्वारा पालन किया जा सकता है । इन विषयों पर मत विभाजन के दौरान सदस्यों को विशेष ढंग से मतदान करने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं ।

319. शेष विषयों पर मत विभाजन के समय सदस्यों को विशेष विधि द्वारा ही मतदान करने के निर्देश देन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

320. यदि वस्त्री अनुसूची में इस प्रकार के प्रावधानों को समिलित कर दिया जाए तो हम वह उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया गया है तथा यह कानून मूलभूत अधिकारों के प्रधाय में उल्लेखित सिद्धान्तों व दूसरे देशों में संसदीय तथा लोकतान्त्रिक प्रणालियों में अनुपालित सिद्धान्तों को विधान मण्डल के सदस्यों को और अधिक सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने में सहायक होगा ।

#### कानून में अन्य प्रावधान :

321. कानून में कुछ अन्य ऐसे प्रावधान हैं जिनकी आलोचना की गई है तथा जिन्हें विधान मण्डलों में कार्य करने वाले और अन्य लोगों द्वारा पसन्द नहीं किया जाता ।

322. कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें परिष्कृत और सुगम बनाने की आवश्यकता है ।

323. कुछ स्वागतयोग्य प्रावधानों को इसमें शामिल करके इस कानून को और अधिक कठोर व प्रभावी बनाया जा सकता है ।

#### इस प्रयोजनार्थ समिति :

324. उपर्युक्त प्रयोजनों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भी दस्ती अनुसूची से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए केवल कार्यपालिका, राज्य-कार्यपालिका के प्रतिनिधियों, विधान-मण्डलों के पीठासोन अधिकारियों के प्रतिनिधियों तथा विधायिकों, संसदीय एवं विधायी मामलों में दक्ष न्यायिकों एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके एक समिति गठित की जा सकती है तथा को जानी चाहिए तथा उस समिति को कानून में निहित खालियों एवं तत्सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के बारे में कम सनय में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है । तत्परता से कार्यवाही की जा सकती है ।

क्या हम कोई अन्य उपाय अपना सकते हैं ?

325. क्या इन उद्देश्यों के लिए हम कोई अन्य उपाय प्रपना सकते हैं ?

326. क्या हम संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़ सकते हैं जिससे उस किसी के कानून रखने की आवश्यकता न पड़े, जिस प्रकार के अब है ।

327. ऐसे संकेत हैं कि ऐसा संभव है और किया जा सकता है ।

328. वास्तव में यह कैसे किया जा सकता है, इस स्थान पर विस्तार में इस बात की चर्चा करने की न तो आवश्यकता है और न ही ऐसा किया जा सकता है । स्मरणीय और प्रष्टव्य बिन्दु यह है कि इस सुझाव पर अमल संभव है और उसकी जांच की जानी चाहिए और यदि वह अवधारिक हो तो उस पर अमल होना चाहिए ।

#### आदेश

1. यह अभी निर्धारित किया जाता है कि संसद के 20 सदस्य जिन्होंने “श्री एक” अंकित आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, 7-8-1992 को संसद के सदस्य थे ।

2. आवेदन में उनके द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार्य है और इस समय मौजूदा सांसदों के संबंध में स्वीकार की जाती है ।

3. भारत के संविधान की दस्ती अनुसूची और लोकसभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर अनहृत) नियम, 1985 के अंतर्गत यह फैसला किया जाता है—

(एक) कि सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चंद्र मुण्डा, गुलाम मोहम्मद और राम बदन लोक सभा के सदस्य के रूप में अनहृत हो गये हैं और इन आवेदन की तिथि में वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं;

(दो) कि श्री वी.पी. सिंह द्वारा सर्वश्री अनादि चरण दास, सूर्य नारायण यादव, रामलखन सिंह यादव, राम शरण यादव, रोशन लाल, अर्जुन सिंह यादव, अभय प्रताप सिंह और उपेन्द्र नाथ वर्मा संसद सदस्यों के विशद् दायर की गई याचिकाएं;

(तीन) कि श्री श्री कान्त जैना द्वारा सर्वश्री अजीत सिंह, रणेन्द्र मसूद, हरपाल पंवार और सत्यपाल सिंह यादव, संसद सदस्यों के विशद् दायर याचिका;

(चार) कि श्री श्रीकान्त जैना द्वारा सर्वश्री राजनाय सोनकर यास्त्री, राम निहोर राय, राम प्रवध एवं श्री शिव शरण वर्मा के विशद् दायर याचिका;

इस आधार पर रद्द की जाती है कि 7-8-1992 को जब वो लोग दल में शलग हुए उस समय वे सभी लोक सभा के सदस्य थे और उनकी सदस्य संख्या जनता दल विधायी पार्टी की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग के बराबर थी ।

इस आदेश की प्रतियां याचिकावातारों, अवक्षियों/सदस्यों, जिनके संबंध में याचिकाएं वो गई हैं तथा लोक सभा में जनता दल के विधायी पार्टी के नेता को अप्रैषित की जाएं ।

(शिवराज वी. पाटिल)  
संसद भवन,  
नई दिल्ली ।  
तिथि—1 जून, 1993  
(शिवराज वी. पाटिल)  
मध्यक, लोक सभा ।

[सं. 46/1/92/टी.]

सी.के. जैन, महासचिव

**LOK SABHA SECRETARIAT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 1993

S.O. 350(E).—The following Decision dated 1 June, 1993, of the Speaker, Lok Sabha, given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

**BEFORE HONOURABLE SPEAKER LOK  
SABHA**

In the matter of application filed by 20 Members of Janata Dal Legislature Party on 7 August 1992

&

In the matter of four petitions filed by Shri V. P. Singh against S|Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan, MPs

&

In the matter of eight petitions filed by Shri V. P. Singh against S|Shri Anadi Charan Das, Suryanarayan Yadav, Ramlakhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Abhay Pratap Singh and Upendranath Verma, MPs

&

In the matter of two composite petitions filed by Shri Srikant Jena against (i) S|Shri Ajit Singh, Rasheed Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav and (ii) S|Shri Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shivsharan Verma, MPs.

**FACTS**

**MAIN POINTS IN THE PLEADINGS**

1. The Janata Dal got 59 Members elected to the Tenth Lok Sabha. Shri V. P. Singh was the Leader of the Janata Dal Parliamentary Party.

2. On 7-8-1992, S|Shri Ramlakhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Ram Sundar Das, Upendranath Verma, Suryanarayan Yadav, Govind Chandra Munda, Anadi Charan Das, Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, Abhay Pratap Singh, Ghulam Mohammed Khan, Ramnihore Rai, Ram Badan, Ram Awadh, R. Sonker Shastri, Shivsharan Verma, Satyapal Singh Yadav, Arjun Singh Yadav, and Roshan Lal gave an application to the Speaker asking that they should be given separate seats in the Lok Sabha. It is marked as "D1"

3. The application bore the signatures of the above mentioned 20 Members of the Lok Sabha and also four more signatures. These four signatories did not accompany the 20 Members when the application was delivered to the Speaker.

4. The 20 Members were asked to sign the application again, confirming that they had put their signatures on the application of their free will.

5. A photocopy of the said application was sent to Shri V. P. Singh for his comments.

6. Shri V. P. Singh filed his written statement on 11-8-1992.

7. In essence what is stated in the written statement is as follows :

- (i) S|Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav, all Members of the Lok Sabha, were expelled from the primary membership of Janata Dal By Shri S. R. Bommai, President of the Janata Dal. Shri Ajit Singh was expelled on 26-12-1991. The three others were expelled in the month of January 1992.
- (ii) S|Shri R. Sonker Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shivsharan Verma, all Members of the Lok Sabha, were expelled from the primary membership of the Party by Shri S. R. Bommai, President of the Janata Dal on 19-7-1992.
- (iii) As such, the eight Members mentioned above had also lost their membership of Janata Dal Legislature Party.
- (iv) They could not thus form part of the group of 20 Members seeking to separate from their original Party i.e. Janata Dal.
- (v) S|Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan, all Members of the Lok Sabha, had violated the whips issued to them, for voting in favour of the No Confidence Motion moved against the Government on 17-7-1992. Under the provision of Rule 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India, they had incurred disqualification, and they had ceased to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992.
- (vi) Thus, out of 20 Members, 12 Members had incurred disqualification, and ceased to be the Members of the Lok Sabha.
- (vii) S|Shri Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav—all eight Members of the Lok Sabha, could not form a group of Members consisting of 1/3 of Members of Janata Dal Parliamentary Party who could separate from Janata Dal as per the provision of para 3 of the Tenth Schedule of the Constitution of India. They too had incurred disqualification under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule and ceased to be Members of Lok Sabha from 7-8-1992.
- (viii) So, the Application of the said 20 Members should be rejected.

8. In terms of para 2(1)(b) of the Tenth Schedule, Shri V. P. Singh filed petitions against S|Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan, all Members of the Lok Sabha, on 11-8-1992.

9. In essence, the relevant points in the petitions are identical. They are as follows :

- (i) The Respondents were directed to vote in favour of the No Confidence Motion moved against the Government.
- (ii) On 17-7-1992, voting took place on the said Motion.
- (iii) The Respondents abstained from voting and violated the whip issued to them voluntarily.
- (iv) Therefore, they incurred the disqualification and ceased to be the Members of the Lok Sabha from 17-7-1992.
- (v) The Petitioner sought a declaration to that effect.

10. The Respondents filed their written statements on 19-8-1992.

In essence, they state that :

- (i) They had not violated the whips voluntarily.
- (ii) They tried to vote on the Motion as per the directions of the Party;
- (iii) But, due to the reason, given in para 11 of each of the written statements, they could not abide by the whips issued to them.
- (iv) Their acts were involuntary and so they were not liable to be disqualified.

11. In Para 11 of his written statement, Shri Ram Sundar Das says, in essence that—

- (i) On the day of voting on the No Confidence Motion, he was resting in the Library of the Parliament, as he was not well due to Blood Pressure.
- (ii) When the Division Bell rang, he rushed to the Lok Sabha Chamber.
- (iii) However, by the time he reached the entrance of the Lok Sabha Chamber, the doors were closed and he could not enter the House.
- (iv) He wanted to vote in favour of the Motion, but could not.
- (v) His act of not voting was involuntary.
- (vi) So, he was not liable to be disqualified.

12. In para 11 of his written statement, Shri Govind Chandra Munda, in essence, says that—

- (i) He was not well on July 15, 16 and 17, 1992 and was suffering from acute pain in his neck and body due to cervical spondylitis.
- (ii) On 17-7-1992, he attended the morning Session of the Lok Sabha. But, in the afternoon, he went to his house because he felt unwell and took some ~~herbal~~ medicine which made him unconscious.
- (iii) He wanted to vote on the Motion. He had kept his Party leader informed that if he was

required to be present in the House to vote, he should be taken in an ambulance with the approval of the Doctor, to the Lok Sabha, to vote on the Motion. But that was not done.

- (iv) His abstention from voting was involuntary.
- (v) So, he was not liable to be disqualified.

13. In para No. 11 of his written statement, Shri Ghulam Mohammed Khan, in essence, says that—

- (i) He was suffering from Diabetes and other ailments and was not well on 17-7-1992 and on two days before that date;
- (ii) He was admitted in the Ram Manohar Lohia Hospital and was in the Hospital on 17-7-1992.
- (iii) He wanted to vote on the Motion.
- (iv) So, he had informed the Party Leader that if his presence in the House was necessary, he could be taken to the House, with the consent of the Doctor.
- (v) His act of not voting was involuntary.
- (vi) So, he was not liable to be disqualified.

14. In para 11 of his written statement, Shri Ram Badan says that—

- (i) He was present in the Lok Sabha on 17-7-1992 and pressed the Button, supporting the Motion.
- (ii) His eye sight is weak. So he could not see on the Board to find out if his vote was rightly recorded.
- (iii) He asked the attendant in the House, who was giving slips to the Members to correct their votes wrongly recorded, if his vote was recorded. And he was informed by the attendant that his vote was recorded.
- (iv) Afterwards, he found out that his vote was not recorded.
- (v) He wanted to vote in favour of the Motion.
- (vi) He did not violate the whip voluntarily.
- (vii) Hence, he was not liable to be disqualified.

15. In terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule, on 22-8-1992, Shri V. P. Singh filed eight petitions against S/Shri Ramsharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav, all Members of the Lok Sabha.

16. In essence, the contents of the Petitions are identical, except the names of the Respondents and are as follows :

- (i) S/Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, Satyapal Singh Yadav, R. Sonker Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shivsharan Verma were expelled from the primary membership of Janata Dal, by the

President of the Party Shri S. R. Bommai. So, they had lost their membership of the Legislature Party. They formed one group.

- (ii) S|Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Budan had violated the whip issued to them on 17-7-1992 and had incurred liability of disqualification under 2(1)(b) of the Tenth Schedule and ceased to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992. They formed the second group.
- (iii) The eight respondents formed the third group.
- (iv) The three groups could not form one composite group of Members to be able to separate from the Janata Dal, without incurring the liability of disqualification.
- (v) The Respondents could not enjoy the immunity provided in para 3(a)(i) of the Tenth Schedule, as they were not one third of the 51 Members of Janata Dal, on 7-8-1992, as the eight Members who were expelled and the four Members who had ceased to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992, could not be counted in the group alongwith them.
- (vi) Janata Dal was not split outside the Parliament, as required, to allow the Legislature Party of Janata Dal to split legally.
- (vii) The Petitioner prays for declarations that the Respondents are disqualified and cease to be Members of the Lok Sabha from 7-8-1992.

17. The Respondents filed their written Statements on 31-8-1992.

18. In essence, they state that—

- (i) The eight Members could not be expelled by the Party Leaders as per the Tenth Schedule of the Constitution of India.
- (ii) The four members had not voluntarily abstained from voting and had not entirely violated whips and had not lost their membership of the Lok Sabha.
- (iii) On 7-8-1992, Janata Dal Legislature Party had 59 Members.
- (iv) On 7-8-1992, Janata Dal Legislature Party had split.
- (v) 20 Members who had formed one group and were more than 1/3 of the Members of Janata Dal Legislature Party and sought permission to sit separately and split the party, had not incurred disqualification and did not cease to be Members of the Lok Sabha in view of the provision of para 3(a)(i) of the Tenth Schedule of Constitution of India.
- (vi) Ajit Singh faction claimed to be the original Janata Dal.

(vii) Hence, the petitions deserved to be disallowed.

19. On 3-10-1992, Shri Shrikant Jena, Member of Lok Sabha and Chief Whip of the Janata Dal Parliamentary Party filed one petition against S|Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav, in terms of para 2(1)(a) and 'under para 6 of the Tenth Schedule.'

20. In essence, the main points made in the Petition are that—

- (i) the Respondents claimed that on 5-2-1992, the Janata Dal was split and Shri Ajit Singh was endorsed as the President of the Party.
- (ii) When the split took place on 5-2-1992, there were only four Members from the Lok Sabha who were part of the group splitting the Party.
- (iii) The four Members were not equal to 1/3 of the Members of Janata Dal in Lok Sabha to enjoy immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.
- (iv) Four Members of the Janata Dal had incurred disqualification and lost their membership of Lok Sabha on 17-7-1992 for having violated the whips.
- (v) The Petitioner had stated that the four Respondents and other four Members were expelled from the primary membership of Janata Dal and as such had lost their membership of Janata Dal in Parliament.
- (vi) In view of the clear admission given by the Respondent that they had split the Party on 5-2-1992, in the written statements filed by them and in the statements given before the Election Commission, the Petitioner prays that the Respondents be declared to have incurred disqualification and lost their membership of the Lok Sabha with effect from 5-2-1992.

21. The Respondents filed their written statement on 4-11-1992.

22. In essence, the Respondents' stand is that—

- (i) The Petitioner cannot be allowed to approve and reprobate.
- (ii) The Petitioner cannot say that the Respondents are not Members of Janata Dal and Janata Dal Parliamentary Party, as they were expelled from the Party and also that they should be declared as disqualified and ceased to be Members of the Lok Sabha from 5-2-1992.
- (iii) The Group of Respondents is the original Janata Dal and as such all the Members of the Party in Parliament belong to their group unless and until they specifically declare otherwise.
- (iv) The Respondents deny other contents of the Petition.

(v) The Respondents pray that the Petition be dismissed.

23. On 3-10-1992, Shri Shrikant Jena, Member of Lok Sabha and Chief Whip of Janata Dal Parliamentary Party filed one petition against Shri R. Sonker Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shivsharan Verma, all Members of Lok Sabha, in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

24. In essence, the Petitioner says that—

- (i) Shri Ajit Singh and three others and the Respondents in this case were expelled by the Party.
- (ii) Shri Ram Sundar Das and three others had violated the whips and incurred disqualification and ceased to be the Members of the Lok Sabha from 17-7-1992.
- (iii) Shri Ajit Singh and three other Members of Parliament claimed in clear terms that on 5-2-1992, they had split from Janata Dal and that they belonged to the faction which was the original Janata Dal. This claim was made by them in the written statements filed by them and also the statements filed by them before the Election Commission.
- (iv) Thus, Shri Ajit Singh and other three Members formed a separate Party in terms of para 3(b) of the Tenth Schedule.
- (v) On 7-8-1992, 20 Members filed an application before the Speaker, seeking a declaration that they had split and asking for separate seats in the Lok Sabha.
- (vi) As Shri Ajit Singh and three other Members had formed a separate Party, they could not be a part of the group of Janata Dal, separate seats in the Lok Sabha.
- (vii) Remaining 16 Members could not be a group consisting of 1/3 Members of Janata Dal in Parliament. So, they incurred disqualification.
- (viii) The Respondents thus incurred disqualification and ceased to be Members of the Lok Sabha with effect from 7-8-1992 in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule for having not acquired the immunity in terms of 3(a)(i) of the same.

25. The Respondents filed their written statements on 4-11-1992.

26. In essence, the stand of the Respondents is that—

- (i) The Petitioner should not be allowed to approbate and reprobate.
- (ii) They claim immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule.
- (iii) The faction of Janata Dal to which they belong is the original Janata Dal and as such all the Members of Janata Dal in Parliament belong to their faction unless they claimed otherwise.

(iv) All other contents regarding expulsion and disqualification on the ground of violation of whips by other Members and also other contents are denied.

(v) The Respondents pray that the Petition be dismissed.

#### HOW THE PROCEEDINGS WERE CONDUCTED ?

27. The application given by the 20 Members and 12 Petitions filed by Shri V. P. Singh and 2 Petitions by Shri Shrikant Jena, have many common points. Therefore, with agreement between the Parties, it was decided that all the Petitions and the application would be heard and decided jointly.

28. The Parties to the dispute were allowed to plead their cases themselves as well as through their lawyers. They filed their pleadings, examined the witnesses and argued on points of law and facts through their lawyers, who did their tasks excellently cordially and justly.

29. Broadly, the Civil Procedure Code was followed in conducting the proceedings.

30. Wherever it could not be followed, the principles of natural justice were followed.

31. The leaders of the political parties in the Lok Sabha were allowed to put forth their views on legal points orally as well as in writing.

32. The proceedings were allowed to be watched and reported by the Press and the media.

33. Documentary and oral evidence was adduced and produced by the Parties.

34. The lawyers of the Parties advanced detailed arguments which continued for about 20 hours.

35. The evidence and the arguments were recorded verbatim. They are available on audio cassettes too.

36. The pleadings, the evidence and the arguments are compiled in the form of paper books.

37. The points at issue were listed and on them evidence was allowed to be produced and arguments were heard.

38. The points at issue were finalised after hearing the Parties. The Parties, however, did not strictly follow the points at issue while arguing the case.

The decision in the subsequent paras gives findings on the issues in a general manner.

#### ISSUES

##### ISSUES RELATING TO DOCUMENT D1

- (i) Is D1 filed under the Constitution of India, any other Law or the Rules of Procedure of Lok Sabha ?
- (ii) What do the signatories claim under D1 ?
- (iii) At what time and in what manner the claims under the Tenth Schedule of the Constitution of India are to be proved ?

- (iv) Can the Leader of a Political Party expel a Member of his Party and terminate his Membership of the Legislative Party, so as to change his rights, obligations and immunities given under the Constitution of India, other Laws or the Rules of Procedure in Lok Sabha ?
- (v) What is the significance of the Members sitting separately at the instance of their Party Leader on their expulsion from their Party ? Does it have any significance for interpreting and enforcing the Tenth Schedule of the Constitution of India ?
- (vi) What is the significance of the Members sitting separately at their own instance ? Does it have any significance for interpreting and enforcing the Tenth Schedule of the Constitution of India ?
- (vii) What Order ?

#### ISSUES RELATING TO VIOLATION OF WHIP

- (i) Does the Petitioner prove that the Respondent violated the Whip voluntarily and if so, the Respondent ceased to be a Member of Parliament with effect from 17-7-1992 ?
- (ii) Does the Respondent prove that he did not voluntarily refrain from voting ?
- (iii) What Order ?

#### ISSUES RELATING TO VOLUNTARILY GIVING UP THE MEMBERSHIP OF THE POLITICAL PARTY

- (i) Does the Petitioner prove that the Respondent has become liable to be disqualified under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India by being a signatory to Document D1 ?
- (ii) Does the Respondent prove that the immunity provided by para 3 of the Tenth Schedule is available to him ?
- (iii) What Order ?

#### ISSUES RELATING TO THE CASE OF SHRI AJIT SINGH AND THREE OTHERS

- (i) Does the Petitioner prove that Shri Ajit Singh and three others have become liable to be disqualified under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India, by constituting a separate faction of the Janata Dal Party ?
- (ii) Do the Respondents prove that the immunity granted by para 3 of the Tenth Schedule is available to them ?
- (iii) What Order ?

#### ISSUES RELATING TO THE CASE OF SHRI RAJNATH SONKAR SHAstri AND THREE OTHERS

- (i) Does the Petitioner prove that Shri Rajnath Sonkar Shastri and three others have become liable to be disqualified under para

2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India, by being a signatory to the Document D1 ?

- (ii) Do the Respondents prove that the immunity granted by para 3 of the Tenth Schedule is available to them ?
- (iii) What Order ?

#### LAW POINTS

39. By and large, following were the law points which came up for discussion through the course of proceedings.

#### HOW THE LAW OF ANTI-DEFECITION SHOULD BE INTERPRETED ?

40. The Tenth Schedule of the Constitution of India is treated and popularly known as the law of anti-defection.

41. It is framed to curb and control the menace of crossing of the floor by the elected representatives of the people in Legislatures.

42. Before it came into existence, the legislators could vote as they liked, could leave their parties and could join other parties, without incurring any liability or disqualification or losing their membership of the legislature. They enjoyed right to freedom of voting, joining or forming any party. The right was identical with the right enjoyed by other citizens. The same kind of right is enjoyed by the Members in Parliaments in other countries.

43. However, the right was misused and abused. It was used to destabilise and form Governments on principles which were capricious and unethical.

44. Therefore, the present law was framed to contain the menace of defection.

45. It creates obligations and rights for the legislators.

46. It enjoins that the legislator has to vote according to the whip issued to him by his party, has not to leave his party, has not to form any party, has not to join any party. If he violates these obligations, he can be declared as disqualified to be the member of the legislature and lose his membership of the legislature.

47. These obligations are not absolute. They are relaxed by the same law which creates the obligations. The legislator can vote as he likes in violation of the whip issued to him, if 1/3 Members of his Party in the legislature wish to vote alongwith him differently from the direction given by the Party. He can separate from his party and form a new party, without incurring any disqualification, in company of 1/3 Members of his Party in legislature, on a split in his party. He can merge with any other party without incurring any disqualification in company of 2/3 members of his party in the legislature. These rights are given to him because they were available to him, before the Tenth Schedule came into existence as such rights are necessary in democratic and parliamentary systems, because such rights are enjoyed by

the citizens under PART III of the Constitution of India and also because such rights are available to the legislators in Parliaments and legislatures of other countries.

48. Therefore, the provisions of the Tenth Schedule have to be interpreted very meticulously and strictly.

49. The interpretation can influence very wide and long range of activities and large number of institutions and individuals. The laws creating rights and obligations for citizens and a class of persons and in re so for elected representatives of the people have also to be interpreted very carefully and strictly.

50. That which is not in the Tenth Schedule cannot be introduced in it.

51. The provisions of the Party Constitution cannot be read and introduced in the Tenth Schedule.

52. Some provisions of the Tenth Schedule cannot be interpreted to frustrate other provisions of the same.

53. The provisions of the Tenth Schedule have not to be used in a colourable manner.

#### EXPULSION :

54. The stand of the petitioners was that the leader of the political party could expel the members of the party from their primary membership and if it was done, the members lost their membership of the party in legislature also.

55. They contend that the expulsion could be effected under the provisions of their Party Constitution.

56. They concede that there was no provision in the Tenth Schedule or any other law or rules under which they could expel the members.

57. They asserted that the expelled members could not form part of the group intending to separate from the original party to make it equal to a group having 1/3 members of the party in legislature.

58. They held that the Speaker did not have any authority to look into the matter of expulsion. He could not try to ascertain if the procedure provided in the Party constitution to expel the members was followed or not. And yet he was, according to them, expected to disown the Members from the group of members having a right to split from the original party in 1/3 number of members of the party in legislature.

59. They were of the opinion that if that was not allowed to be done they would be unable to keep their Party in tact and discipline their members.

60. They thought that there existed a contractual obligation between the Party members and their party as a whole, which could not be adjudicated upon by courts of law or the Speaker, for that matter.

61. They held that the relationship between the Members of a Club and the Club was identical with

the relationship between the Members of a Party and the Party.

62. It is difficult to concede the views expressed by the Petitioners on this point in the manner mentioned above.

63. In this respect, Explanation (a) to para 2(1) is relevant :

"(a) an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member."

This a constitutional status given to the Member which cannot be taken away from him by expulsion.

64. A Member of the Legislature comes to the House, not only because he was given the ticket by his Party, but because he was elected by the voters also. He is not only obliged to the Party but he is also obliged to the voters.

65. If there is a contract, the contract is not between two Parties. It is tripartite contract. A contract between the Member, his Party and the Voters. His obligation to voters is greater than this obligation to his Party.

66. His rights and obligations as a Member of his Party may arise out of the Constitution of his Party. Therefore, for party purposes, he is bound by the Party Constitution.

67. His rights and obligations as a Member of the Legislature emanate from the Constitution of India and other relevant laws and rules. For the purpose of his Parliamentary rights and duties, he is bound by the Constitution of India, the Tenth Schedule and other relevant laws. His party constitution cannot have an upper hand over the Tenth Schedule or other parts of the Constitution of India or other statutes and rules of procedure made by the Legislature.

68. The Party Constitution cannot add to or reduce from rights and duties given to the Member of the Legislature under the Constitution of India and other relevant laws.

69. The Tenth Schedule is framed to curb and control the menace of floor crossing and is relevant to the activities of the Member as a Parliamentarian, and to his commissions, omissions, and activities in the legislature rather than to his activities as a party member outside the legislature, not connected with parliamentary activities.

70. The Speaker has no right or duty to help the leaders of the parties to keep their parties in order and discipline their members.

71. A legislator may discharge his duties as a Member of his Party. He may do his duties as a Legislator. The Tenth Schedule applies to his duties and rights as the Legislator. It does not apply to his rights and duties as a Party Member.

72. The Party leader may expel his Member from his Party and may not give him his party facilities.

He may not give him ticket in the next election. He may not give him party positions and posts. He may not give him opportunities to attend party meetings. He may not be given opportunities to be Member of Committees or institutions as a Party Member.

73. But, the Party leader cannot deprive the legislator of rights and facilities which can be available to him because of the fact that he is elected and because of the provisions in the Tenth Schedule, the Constitution of India, other relevant laws and rules.

74. The provision in the Party Constitution cannot be read as the provisions and part and parcel of the Tenth Schedule and the Constitution of India.

75. The Constitution of India or the Tenth Schedule have not to be interpreted to suit the Parties and to fit in their constitutions.

76. The Speaker is not to be bound by the Party Constitution. He has to function in accordance with the Tenth Schedule, the Constitution of India and other relevant laws and rules.

77. In the Lok Sabha, there are 23 Parties. They have their own constitutions, which are and can be amended in a manner they like. It is not possible to find out if they are amended as per the procedures laid down for the purpose.

78. The Speaker is not expected to allow them, or be bound by them. If that is done, the result would be very confusing.

79. Therefore, it can be held that as there are no provisions in the Tenth Schedule of the Constitution of India or in any other part of the Constitution of India, or in any other relevant laws or Rules of Procedure followed in the Lok Sabha for the purpose of parliamentary functioning and with respect to his rights and duties as a Member of the Legislature and not for his party rights and duties and functioning, a Member of a Party elected to a Legislature by the voters, under the Constitution of India and other relevant laws cannot be expelled.

80. It is not correct and legal to hold that if a Member of a Party is expelled from its primary membership, he loses his membership of his legislature party.

81. It is not correct and legal to hold that the Party leaders can alter the obligations and rights of the Legislators given to them by the law, by expelling them from their primary membership under their Party constitution.

82. In the past, members were expelled to achieve different objectives.

83. Members of the Legislature should be allowed to be expelled for the purpose of implementing the Tenth Schedule, only if there are provisions for the purpose in the Tenth Schedule and not otherwise.

84. As there are no provisions in the Tenth Schedule or any other part of the Constitution, the expulsion of the Members for parliamentary purposes is not legal and cannot be allowed.

85. The Petitioners realised the legal position correctly and conceded this interpretation of the law.

86. That is why, they have filed petitions against eight members who they claimed were expelled and were not Members of their Legislature Party. By doing so, they have conceded that for parliamentary purposes, the elected members of the legislature cannot be expelled by the Party leaders under their Party constitution.

87. Though a little ambiguously, this position is treated as correct by the petitioners in their petitions filed against the allegedly expelled members of their party.

#### UNATTACHED :

88. In the past, in some cases, when the Members were expelled, they were called Unattached to distinguish them from the Party Members as well as from the Independent Members.

89. The word Unattached is not used anywhere in the Tenth Schedule or any part of the Constitution of India or any other relevant laws or the Rules of Procedure followed in the Parliament.

90. A Member belonging to a Party has certain rights and obligations under the Tenth Schedule of the Constitution of India.

91. An Independent Member also has certain rights and obligations under the same law.

92. But a Unattached Member does not appear to have any particular status or position.

93. As to what kind of obligations he is subjected to or as to what kind of rights he has is not very clear and is very confusing.

94. Therefore, it is correct to hold the word has no particular legal meaning attached to it and does not create any obligations or rights for the Member who is declared as Unattached.

#### WHEN DOES THE DECISION TAKEN BECOME OPERATIVE :

95. (i) From the date of the decision taken?

(ii) From the date of the Petition filed?

(iii) Or from the date on which the violation of whip takes place or the Party is split or the other Party is joined by the Members?

96. The general rule is that the laws made are procedure.

97. If they are intended to be retrospective, that has to be made clear in specific terms in the laws themselves.

98. When two interpretations can be put on the laws, one giving them prospective character and the second giving them the retrospective character, the interpretation which gives them prospective character has to be accepted.

99. The retrospective nature of law may hurt innocent persons. Hence, making laws retrospective or interpreting them in such a manner that they become retrospective should be tried to be avoided.

100. The Tenth Schedule of the Constitution of India is prospective and not retrospective in nature.

101. The provision in the Tenth Schedule are such that they cannot be interpreted to make them retrospective or the decisions given under them, retroactive.

102. It provides that the Speaker can declare a Member disqualified, if a petition is filed before him for that purpose. He cannot make the declaration without a petition having been filed before him by any Member.

103. The Leader of the Party is expected to give a No ice to an erring Member and ask him as to why a Petition should not be filed against him.

104. If the Member gives a satisfactory reply to his leader, he may condone his lapse in which case no petition can be filed against the erring Member.

105. If a Member is liable to be disqualified and if he joins a Group of Members who are oblivious of the liability of the Member and other Members take a step to separate from their original Party with a belief that they are a group of requisite number of Members and the Member under the liability loses his Membership later on and if the decision given is made retroactive, injustice would be caused to other Members. This kind of situation is expected to be avoided.

106. It is for these reasons, it can justly be held that the Tenth Schedule of the Constitution of India is not of retrospective character and the decisions given under its provisions need not be retroactive or retrospective.

107. In their petitions filed on 11-8-1992 against Shri Ram Sundar Das and three others, the Petitioners pray that the Respondents be declared as disqualified and that they cease to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992, the date on which they violated the whips.

108. The petitioners want the decision to be retroactive.

109. In other petitions also, the prayers are to make the decisions retroactive.

110. All the decisions taken under the Tenth Schedule on the Petitions, shall be operative from the date of the decision and not retrospectively.

PAS THE SPEAKER ANY AUTHORITY TO ADJUDICATE IN THE MATTERS RELATING TO THE PARTY ACTIVITIES AND THEIR LEADERS' DECISIONS OUTSIDE THE PARLIAMENT ?

111. The Tenth Schedule is meant to curb and control the floor crossing by the Legislators.

112. It applies to the Parliamentary activities of the Legislators.

113. If a Legislator violates a whip issued to him, if he leaves his party voluntarily, if he forms a new party or if he joins another party, he is punished under the Tenth Schedule, he is disqualified to be the Member of his Legislature.

114. To punish him, the Speaker can go into the details to ascertain if the whip was voluntarily violated, if the Member left his Party or joined another Party etc.

115. If a Member does not abide by the whip issued to him, in a company of 1/3 Members of his Party in Parliament, or if he leaves the Party in a company of 1/3 Members in his Parliamentary Party or if he joins another Party in a group of 2/3 Members of his Party in Parliament, under paragraph 3 or paragraph 4 of the Tenth Schedule, he would not be punished and subjected to disqualification of his membership of the Legislature.

116. The Speaker can decide if the group consisted of 1/3 or 2/3 Members of the Party of the Legislator in the Legislature and declare if he is or is not disqualified.

117. He has to decide if the Party had issued the whip, whether it was violated voluntarily.

118. He has to decide if the political party had split outside the Legislature.

119. He cannot decide if the political party claiming to be original party is having majority support or not.

120. That can be done by the Election Commission.

121. It is not necessary for him to count the number of Members going with one faction of the other outside the Parliament.

122. It is not necessary for him to find out as to how many Members of Parliament were with one faction or the other, outside the Parliament.

123. He can take cognisance of the fact of split in the Party in the Parliament.

124. But that can be done by him, when it is brought to his notice through a Petition by a Member in the Parliament.

125. In these matters, he does not act suo moto. The leader of the Party is allowed to condone the acts of their party members in the Parliament.

126. The Speaker has to find out if the group separating from the original Parliamentary Party consisted of 1/3 Members of the Party in Parliament or not.

127. He has to find out if the group joining any other Parliamentary Party has 2/3 Members of his Party in Parliament or not.

128. It is not necessary for him to find out if the political party splitting outside the Parliament has 1/3 Members of the Party in the Parliament or not.

129. It is difficult for him to find out on what ideological differences the Party is split.

130. The fact of split is more relevant for him to implement the Tenth Schedule.

131. The jurisdiction of the Speaker is more pronounced with respect to the activities of the Parliamentarians in the Parliament.

132. It is least effective with respect to the activities of the Parliamentarians outside the Parliament.

133. The Tenth Schedule is not meant to control, guide and direct the activities of the political parties and their members and to punish the Parliamentarians for their commissions and omissions outside the Parliament.

134. The Speaker is not expected to dabble in keeping the political parties weak or strong or discipline the Parliamentarians for their party purposes.

135. In party matters relating to the Parliamentarians outside the Parliament, jurisdiction is available to the forums presided over by other authorities and not by the Speaker.

## REASONS ON WHICH THE DECISIONS BASE DOCUMENT MARKED D1

### Document "D1"

136. The application filed by 20 Members of the Lok Sabha on 7-8-1992 seeking separate seats for them to sit in the House cannot be treated as application under the Tenth Schedule of the Constitution of India.

137. It can at best be treated as a piece of evidence which could be used in the petitions filed under the Tenth Schedule.

138. The fact of split of a political party outside the Parliament and inside the Parliament by requisite number of Members cannot be used to obtain a declaration from the Speaker that the Party is correctly and legally split.

139. The same fact can be used as a defence in a petition filed against the members splitting the Party, to show that the group separating from the Party in Parliament consisted of 1/3 Members of the Party in Parliament.

140. The application can be considered under Rule 4 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha which reads as follows :

"4. The Members shall sit in such order as the Speaker may determine."

141. On the day on which the application was given i.e. 7-8-1992, all the signatories to the document were sitting Members of the Parliament belonging to the Janata Dal Parliamentary Party.

142. The plea that Shri Ajit Singh and 3 other Parliamentarians and also 4 other Parliamentarians

were expelled from their primary membership of the party by the President of the Party on the dates which preceded the date on which the application was made and hence on that date i.e. 7-8-1992, they were not the Members of the Janata Dal Party in Parliament and they could not be valid Members of the Group separating from the Janata Dal Party in Parliament, cannot be accepted.

143. Parliamentarians cannot be legally and validly expelled by their party leaders from their primary membership of the party to annul their membership of the Parliamentary Party, to defeat the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution.

144. There are no provisions in the law which envisage that kind of expulsion of the Members of Parliament.

145. Expulsions of the Parliamentarians from their primary membership of the party to cancel their membership of the Parliamentary Party under the party constitution is not valid and acceptable.

146. If that is allowed to be done, the purpose of the provisions in the Tenth Schedule would be frustrated. That would amount to introducing something in the fundamental law of the country from a Party Constitution which can be changed at any time.

147. For the reasons given in other parts of the decision also, it is held that S/Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, Satyapal Singh Yadav, Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv Sharan Verma were Members of Parliament, belonging to the Janata Dal on the relevant date i.e. 7-8-1992.

148. On that date i.e. 7-8-1992, petitions were not filed against them seeking for declaration that they were disqualified and had lost their membership of the Parliament

149. In the written reply to the application filed by the opposite side, it is stated that Shri Ram Sundar Das and three other Parliamentarians had violated the directions given to them to vote in favour of the No Confidence Motion submitted against the Government and that the four Parliamentarians had incurred liability of disqualification for being Members of the Lok Sabha with effect from 17-7-1992. And so, they could not form part of the group validly to bring the number of Members to the requisite level.

150. On 7-8-1992, there were no petitions filed and pending against them complaining that they violated the whips and seeking a declaration of their disqualification for being the Member of the Lok Sabha.

151. On 7-8-1992, they were the validly sitting Members of the Lok Sabha belonging to the Janata Dal Party.

152. In other parts of the decision, it is held that the decisions given in these matters cannot be of retroactive or retrospective character.

153. Hence it can be held that they could legally and validly be the Members of the Group seeking separation from the original party.

154. Against S|Shri Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav, petitions were filed seeking their disqualification on 22-8-1992.

155. However, on the relevant date, i.e. 7-8-1992, there were no petitions filed against them.

156. On the relevant date, they were the sitting Members of the Janata Dal Parliamentary Party.

157. On the relevant date, i.e. 7-8-1992, all the signatories to the application were sitting Members of the Janata Dal in Parliament.

158. Their number was equal to 20 which is more than one third of 59, which is the number of Members of Janata Dal in the Lok Sabha on the relevant date.

159. The signatories to the application in a way indicated that there was a split in the Janata Dal outside the Parliament.

160. The application in a way indicated that there was a split in the Parliamentary Party of Janata Dal in Lok Sabha.

161. Although the averments to these effects were made lukewarmly and a little less lucidly, all the other facts and averments made in the subsequent pleadings by both the Parties go to point out that there was a split in the Janata Dal outside as well as inside the Parliament, which had taken place before and on the relevant date respectively.

162. Therefore, the application can be and is allowed to grant their prayer that they be allowed to sit separately.

#### PETITIONS RELATING TO VIOLATION OF WHIPS AGAINST SHRI RAM SUNDAR DAS AND THREE OTHERS

##### PETITION AGAINST SHRI RAM SUNDAR DAS:

163. Most of the averments of the Petitioner in the Petition are not denied and are accepted by the Respondent.

164. Only point on which the Respondent takes a different stand relates to his abstention from voting.

165. The Petitioner avers that the Respondent voluntarily violated the whip. The Respondent asserts that he did not abstain from voting voluntarily.

166. The respondent says that on 17-7-1992, he was unwell, suffering from variable Blood Pressure and in the afternoon was resting in the Library.

167. According to him, when the division bell rang, he tried to rush to reach the Lok Sabha Chamber but because of his weak health and injury to his leg, he could not arrive at the door before it was closed and so he could not enter the House and vote in favour of the No Confidence Motion, although he wanted to do so, very much.

168. The Respondent examined himself only to prove his assertions.

169. He did not file any other evidence of any kind on any of the points connected with his stand.

170. The distance between the Library and the Lok Sabha Chamber is easily coverable, even by a slow walker, unless the person covering the distance purposely slows down or neglects to cover the distance by talking to the persons in the Central Hall or enroute.

171. The Respondent could have rested in the Lok Sabha, in the manner he could have rested in the Library, for the Library is not place meant for resting and with facilities really to rest in a proper manner.

172. The Respondent should have understood the contingency in which he finds himself and should have remained in the House to vote on the Motion.

173. The plea taken by him is not convincing and acceptable.

174. It is therefore, concluded that his act of abstention from voting was not involuntary.

175. The Respondent has become liable to disqualification in terms of para 2 (1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India and ceases to be the Member of the Lok Sabha from the date of this decision.

#### PETITION AGAINST SHRI GOVIND CHANDRA MUNDA

176. The only point in dispute in this Petition also relates to the abstention from voting by the Respondent on the No Confidence Motion against the Government on 17-7-1992.

177. According to the Respondent, he wanted to vote on the Motion and was in the Parliament House in the morning of the said date.

178. In the evening, he felt unwell because of the cervical spondilitis and other reasons also and so he went to his house to take medicine and rest.

179. At his house, he took some herbal medicine which made him unconscious. So he could not go to the Parliament and vote on the Motion.

180. He says he had also informed the Leader of his Party to take him to the Lok Sabha, in Ambulance with the consent of the Doctor, if it was necessary for him to attend the House. But nothing in that respect was done.

181. The Respondent examined himself and other witnesses in support of his stand. They were cross examined by the lawyer of the Petitioner.

182. He produced some documentary evidence also to prove his plea.

183. The stand of the Respondent is not convincing and acceptable.

184. The evidence given by him is contradictory and not acceptable.

185. The evidence given by his witness is also not convincing and acceptable.

186. There are contradictions between his documentary and the oral evidence.

187. There are contradictions in the evidence given by him and his witnesses.

188. Illness which he suffered from was not such that he could not have gone to the Lok Sabha Chamber to vote.

189. If he had really wanted to vote, he could have organised to be in the Lok Sabha, just at the time of voting and then retired to his house for rest or to the Doctor for medical assistance.

190. His plea that he had asked the Leader of the Party to take him to the House in a vehicle with the permission of the Doctor, if his presence in the House was a must, is not acceptable. He could have gone to the Lok Sabha Chamber on his own, without asking his Leader to take him there. His asking the Leader to take him to the House appears to be an attempt to shift the responsibility to some one else for his default.

191. As a responsible Member of the House, he could have remained present in the House and voted.

192. The fact that he went to his village in Orissa next day itself goes to show that he was not in a very bad shape on the relevant date.

193. The plea that he had asked his Party leader to take him to the House, if need be, appears to be device invented to overcome the difficulties arising out of his absence, in consultation with another Member.

194. The demeanour of the witness suggested that they were making artificial statements.

195. In view of the unconvincing pleas adopted, evidence given and arguments advanced, it is difficult to hold that the Respondent did not vote involuntarily because of the circumstances beyond his control.

196. It is, therefore, held that he abstained from voting voluntarily and has become liable to be disqualified for being the Member of the Lok Sabha with effect from the date of this decision.

#### PETITION AGAINST SHRI GHULAM MOHAMMED KHAN

197. In this petition also, the point in dispute is identical to that in dispute in other three cases.

198. The Respondent pleads that on 17-7-1992, he was not well and was in Ram Manohar Lohia Hospital and suffering from diabetes and other ailments.

199. He says that he had informed the Leader of his Party that if his presence in the House was essential he should be taken there with the consent of the Doctor.

200. He states that he intended to vote on the Motion, but he could not do so because of conditions beyond his control.

201. He examined himself and other two witnesses to prove his stand. He and other witnesses were cross-examined by the Lawyer of the Respondent.

202. He produced some documents to support his plea.

203. He came back to his house on 17-7-1992. This fact contributes towards strengthening the belief that he was not in a very bad shape on 17-7-1992.

204. His stand that the leader of the Party should take him to the House, with the consent of the Doctor, is the kind of stand taken by Shri Govind Chandra Munda, a Respondent in the other Petition.

205. It is not convincing and acceptable. What he is asking his leader to do, he could have done himself.

206. It appears to be a part of the attempt to shift the responsibility from himself to someone else.

207. As a responsible Member of the House he should have taken care to be present in the House to vote.

208. As he was in New Delhi, it could not have been difficult for him to attend to duties of voting in the House.

209. The evidence given by him is not convincing.

210. The evidence given by other witnesses also does not evoke great confidence. Their approach appears to be casual and not convincing.

211. There are some contradictions between his oral and documentary evidence.

212. There are some contradictions in the evidence given by him and his witnesses.

213. In view of these facts, the plea adopted by the Respondent that his abstention from voting was involuntary cannot be accepted.

214. Therefore, it is held that he has become disqualified to be the Member of the Parliament with effect from the date of this decision.

#### PETITION AGAINST SHRI RAM SHARAN

215. The Respondent pleads that on 17-7-1992, he was in the Lok Sabha and he did press the Button to vote in favour of the Motion and that because of the defect in the machine, his vote was not recorded.

216. He says he asked the attendant in the House if his vote was recorded on the Board or not. According to him, the attendant informed him that it was recorded.

217. He says that his eye sight is weak and so he could not see the Board properly to find out if the vote was really recorded or not.

218. His plea is that he intended to vote but by accident he could not vote.

219. He examined himself to support his plea.
220. He did not examine the attendant in the House as his witness to corroborate his evidence on his plea.
221. The plea of the Respondent is not convincing and acceptable.
222. The evidence produced by him is not convincing.
223. And so, it is not possible to hold that his abstention from voting was involuntary.

224. It is, therefore, concluded that the Respondent has incurred the liability of disqualification for being the Member of the Lok Sabha with effect from the date of this decision.

#### PETITION AGAINST SHRI RAM SHARAN YADAV AND SEVEN OTHERS

##### EIGHT PETITIONS:

225. On 22-8-1992, Shri V. P. Singh filed Petitions against S/Shri Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Rushan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav, all Members of the Lok Sabha in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

226. The contents of all the petitions are identical. So, they are dealt with jointly.

227. In essence, the petitioner's stand is as follows:

- (i) The Respondent did not claim that there was a split in the Janata Dal Political Party on or before 7-8-1992 and that he belonged to one of the factions.
- (ii) Para 3(a)(i) of the Tenth Schedule contemplates a split in the political party prior to the split in the party in the Parliament, which is not shown to have taken place.
- (iii) Shri Ajit Singh and seven other Parliamentarians were expelled from the Party's primary membership on three dates which preceded the relevant date, i.e. 7-8-1992. So, they had ceased to be Members of the Janata Dal in Parliament on the dates of their expulsions.
- (iv) Shri Ram Sundar Das and three other Parliamentarians had violated the whips issued to them on 17-7-1992. So, they had become liable to be disqualified to be Members of the Lok Sabha with effect from the date on which the whips were violated.
- (v) Thus, the Respondents could not form a group consisting of 1/3 Members of Janata Dal in the Parliament as the Members expelled and the Members disqualified could not form part of the group on 7-8-1992.
- (vi) For these reasons, the Respondents had incurred the liability of disqualification for being the Members of the Lok Sabha with effect from 7-8-1992.

- (vii) The three groups—one consisting of the expelled Members, the second consisting of the Members who had lost their membership of the Parliament for having violated the whips and the third consisting of the Respondents could not come together to form a group to claim the benefit under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.
- (viii) According to the Petitioner, Members who were expelled from the primary membership of their party, by the Party President, lost their membership of the Parliamentary Party from the day of their expulsion.
- (ix) The above position was accepted by the former Speaker who had treated the expelled Members as Unattached Members.
- (x) The President of Janata Dal expelled their Party Members in the Parliament on different dates, having gaps of many days between the days on which they were expelled for anti-party activities.
- (xi) Other Members continued to be Members of the Janata Dal in the Parliament. In fact, some of them participated in the party elections.
- (xii) The Respondents contend that no split in Janata Dal Political Party did take place before or after the eight Members were expelled by the President of the Party.
- (xiii) They say that to claim the immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule, there should be a split in the political party and there should also be a split afterwards in the Parliamentary Party. Without there being two splits, the Members could not enjoy the immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule.
- (xiv) They contend that Shri Ajit Singh did not claim a split in the political party in the pleadings in the Court and also before the Election Commission. His stand was that he was the President of the original Janata Dal.
- (xv) The anti defection law contemplates that there would be a political party and a legislature party.
- (xvi) A split in the Political Party could not be caused by a few Members in the Parliament. It has to be caused by a large number of Members of the Party.
- (xvii) Therefore, it could not be held that there was a split in the political party of Janata Dal as required by the Law.
- (xviii) The conduct of the Respondents in making the application to the Speaker on 7-8-1992 asking for separate seats in the Parliament amounted to giving up the Party as contemplated in para 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

(xix) The prayer by the Petitioner is that the Respondents be declared to have become subject to disqualification and to have ceased to be Members of the Lok Sabha from 7-8-1992.

228. The Respondents filed their written statement on 31-8-1992.

In substance it states that—

- (i) The points raised by the Petitioner were replied to in the pleadings filed by them in other cases.
- (ii) The Respondents claim that they were the Members of the original Janata Dal and that their claim would be proved in other forums.
- (iii) They say that on 7-8-1992, the Parliamentary Party had split, and the group which split consisted of Members equal to 1/3 Members of Janata Dal Parliamentary Party.

229. The claims made by the Petitioners in this case and Petitioners in other cases filed against Shri Ajit Singh and three other Parliamentarians and Shri Rajnath Sonkar Shastri and three others and those made by the Respondents in these petitions and the Respondents in other Petitions are quite confusing and contradictory.

230. In spite of the contradiction in claims made by both sides, there is so much material in their pleadings, evidence and arguments to hold that Janata Dal Political Party had split before 7-8-1992. The material is also contained in the submissions made by the Parties in the Court of Law and also before the Election Commission. Therefore, the Respondents can claim the immunity provided in para 3(a) (i) of the Tenth Schedule.

231. It is already held that the President of the Janata Dal could not expel Shri Ajit Singh and three others from the Parliamentary Party of Janata Dal and could not abridge their rights and duties. They continued to be Members of the Parliamentary Party of Janata Dal.

232. It is also held that Shri Ram Sundar Das and three others were valid Members of the Parliamentary Party of Janata Dal and the Lok Sabha on 7-8-1992. So, they could form part of the group on that date, separating from Janata Dal Parliamentary Party.

233. There is, therefore, no difficulty in holding that Shri Ajit Singh and seven other Parliamentarians, Shri Ram Sundar Das and three other Parliamentarians and the Respondents could form a group consisting of 1/3 Members of Janata Dal in Parliament and could separate from other Members of the Janata Dal Parliamentary Party without becoming liable to be disqualified.

234. The stand of the Petitioner that the expelled Members of the Party lost their membership of the Parliamentary Party is not valid, legal and correct. The reasons why it is not correct are given in the previous paras.

235. The reference to the stand taken in the past to the word "Unattached" is also made in the previous paras. What is suggested by the Petitioner in that respect is not correct and valid.

236. Therefore, it is not possible to hold that the Respondents had become disqualified to be Members of the Lok Sabha in terms of para 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

237. Therefore, the Petitions are dismissed.

#### PETITION UNDER RULE 2(1) (a) AGAINST SHRI AJIT SINGH AND THREE OTHERS

#### PETITION AGAINST SHRI AJIT SINGH AND 3 OTHERS

238. On 3-10-1992, Shri Srikant Jena, the Chief Whip of Janata Dal Parliamentary Party, filed a composite petition against S/Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

239. This petition is not filed by Shri V.P. Singh who was the Leader of the Janata Dal Parliamentary Party.

240. The Petitioner repeats that the Respondents were expelled from their primary membership of Janata Dal by the President of the Party, that other four Members were also expelled for their anti-party activities, and that four other parliamentarians had become disqualified to be Members of the Lok Sabha for having violated the whips issued to them.

241. The Petitioner states that on 7-8-1992, the Respondents and other four expelled Members and other four Members who had become liable to be disqualified and other eight members made an application to the Speaker seeking separate seats for them in the Lok Sabha.

242. He says that Shri Ajit Singh had in very clear terms claimed that on 5-2-1992, Janata Dal had split and he was endorsed as the President of the original Janata Dal.

243. Para 7 of the Petition is very relevant and reads as follows :

"7. That expulsion of a Member of the Parliament by the Party he belongs to does not result in the forfeiture of his Membership of the House, because para 2(1)(c) of the Tenth Schedule which originally was included in the draft legislation was deleted from the Amendment Bill. Petitioner, therefore, did not file a Petition against the Respondents herein for seeking their disqualification from the House immediately after the expulsions orders were passed against him".

244. The Petitioner says that on 5-2-1992, the only four Members formed part of a faction that had arisen as a result of the split.

245. According to him, his act of becoming the President of a faction of the Janata Dal, in the company of only three Members of the Janata Dal Parliamentary Party amounted to giving up his Party. As the four Members were not equal to 1/3 Members of the Janata Dal in Parliament, they became liable to be disqualified to be Members of the Lok Sabha from 5-2-1992.

246. Para 13 of the Petition reads as follows

"13. That the question as to whether the expulsion of the Respondents herein was valid or invalid need not, therefore, be pursued in view of the admission of the Respondents quoted above as a result of which they have incurred the disqualification."

247. It is prayed that the Respondents may be declared as disqualified from being Members of the Lok Sabha with effect from 5-2-1992.

248. The stand of the Petitioner in this Petition is quite contrary to the stand of Shri V.P. Singh in other petitions.

249. The Petitioner treats the Respondents as Members of his Parliamentary Party even on the date of filing his petition i.e. 3-10-1992, and gives up the stand under which his Party used to treat the Respondents and four other Members of his Parliamentary Party as Unattached and not belonging to his Party in the Parliament.

250. The stands contradict each other.

251. The Respondents filed their written statement on 4-11-1992.

252. In essence the stand taken by the Respondents is as follows:

The Respondents repeat what they had said in other Petitions on the points expulsion of eight Members, disqualification of four Members on the ground of violation of the whips and disqualification of eight Members on the ground of having given up their party.

253. They state that they are the Members of the original Janata Dal and as such all others are the Members of the Janata Dal, excepting those who specifically deny to be so.

254. Most other points are denied by them.

255. There is ample evidence in the record to show that there had taken place a split in Janata Dal before 7-8-1992.

256. The Tenth Schedule relates to split in the Parliamentary Party and not the political party outside the Parliament. The law proposes to protect the Parliamentary Party, having elected Members and does not protect the political party outside the House. It is meant to curb defection. It is not meant to protect political parties outside the Parliament.

The Respondents, therefore cannot be declared to have become disqualified on the ground of having left their Party in insufficient numbers on 5-2-1992.

257. Therefore, the Petition deserves to be and is dismissed.

#### PETITION UNDER PARA 2(1)(a) OF TENTH SCHEDULE AGAINST SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI AND THREE OTHERS

#### PETITION AGAINST SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI AND THREE OTHERS

258. On 3-10-1992, Shri Srikant Jena, the Chief whip of Janata Dal Party in Parliament, filed a composite petition against Shri Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv Sharan Verma, in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

259. Out of 14 petitions, 12 are filed by Shri V.P. Singh, Leader of the Janta Dal in Parliament and 2 are filed by Shri Srikant Jena, the Chief Whip of Janata Dal in Parliament.

260. Shri V. P. Singh, contends in almost all the petitions that Shri Ajit Singh and three others were expelled from the primary membership of the Party and so they had lost their membership of the Janata Dal Parliamentary Party and so, they could not form part of the group separating from Janata Dal headed by Shri Bommai as its President to make up the requisite number so that the separating Members do not get disqualified.

261. Shri Srikant Jena contends in this petition and in the petition filed against Shri Ajit Singh and three others that Shri Ajit Singh and three others had in clear terms admitted that on 5-2-1992, they had split from the party headed by Shri Bommai and that a new Party was formed by them on 5-2-1992.

262. If the new Party was formed and if Shri Ajit Singh and three others became the Members of the new Party, they could not join the group on 7-8-1992 to separate from the Parliamentary Party in requisite numbers.

263. Thus, on 7-8-1992, the other remaining Members were only 16 and they could not form a group having the requisite number and hence the Respondents in this petition who were the signatories to the application given to the Speaker on 7-8-1992 could become disqualified for having given up their Party in insufficient numbers.

264. The stand taken by Shri V. P. Singh is contrary to the stand taken by Shri Srikant Jena.

265. The Petitioner asks that the respondent should take a fixed stand and they should not approve and reprobate. However, the Petitioners themselves appear to be approving and reprobating.

266. The faction of Janata Dal headed by Shri S.R. Bommai, appears to have given up the stand that the Members of Parliament can be expelled from the Parliamentary Party.

267. The Respondents filed their written statement on 4-11-1992.

268 Through the written statement they say that Shri Ajit Singh and seven others could not be legally expelled from the Janata Dal Parliamentary Party, that Shri Ram Sundar Das and three others could not be disqualified on the ground that they had violated the whips issued to them.

269 They say that Shri Ajit Singh and three others belonged to the original Janata Dal and as such all other Members of Janata Dal Parliamentary Party belonged to their faction, unless any of them declared specially otherwise.

270 It is already held that the President of the Janata Dal could not expel Shri Ajit Singh and three others from the Parliamentary Party of Janata Dal and could not abridge their rights and duties. They continued to be Members of the Parliamentary Party of Janata Dal.

271. It is also held that Shri Ram Sundar Das and three others were valid Members of the Parliamentary Party of Janata Dal and the Lok Sabha on 7-8-1992. So, they could form part of the group on that date, separating from Janata Dal Parliamentary Party.

272 There is, therefore, no difficulty in holding that Shri Rajnath Sonkar Shastri and three other Parliamentarians and the sixteen other Respondents could form a group consisting of 1/3 Members of Janata Dal in Parliament and could separate from other Members of the Janata Dal Parliamentary Party without becoming liable to be disqualified.

273 The stand of the Petitioner that the expelled Members of the Party lost their membership of the Parliamentary Party is not valid, legal and correct. The reasons why it is not correct are given in the previous paras.

274 Therefore, it is not possible to hold that the Respondents had become disqualified to be Members of the Lok Sabha in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

275 Therefore, when the said application was given to the Speaker, the Members signing it, were in requisite numbers and so the Respondents in the present petition cannot be held to have become subject to disqualification on the ground of having separated from their party in insufficient numbers.

276 Therefore, it is held that the Petition deserves to be and is dismissed.

#### SOME THOUGHTS ON THE CASE AND THE LAW

How Important, how complicated and how agonising are the matters in this case ? Moral, Legal, Political aspects of it.

277. This matter is important and complicated. It has been a little agonising also.

278 It is important because it has implications for the Democracy and Parliamentary system in India.

279 It is complicated because it involves interpretation of The Tenth Schedule of the Constitution of India and the freedoms, rights and obligations enjoyed by the Indian citizens and their representatives in the Parliament.

280 The Tenth Schedule is a new law. There are not many precedents available on the basis of which it can be interpreted and enforced. It is not happily worded nor free from lacunae.

281 The totality of the matter consists of one application and fourteen petitions. Some pleadings in the petitions and applications have been contradictory and casual too.

282 The Parties to the matter are not expected to be clear on the law points involved in it. Their approach has been political rather than legal.

283 It has been agonising because, at times, words were used by the Parties which could hurt. However, it has been ultimately dealt with in a responsible manner by all concerned. The lawyers appearing in the case have been able to shed light and bring restraint and logic to bear on the proceedings.

284 The matter has moral, legal and political ingredients, according to some.

285. It is not easy to pass judgments in matters moral. Those who have to deal with matters on the basis of law have restricted scope to apply the principles of morality while deciding the issues. There may occur contradictions between the stands moral and the stands legal, taken by the Parties. In such cases, as per the rule of law, the stands legal get the upper hand. Those who have to decide have to do their best to keep the principles of morality in their minds while giving judgments on the basis of law.

286 The matters of this nature have to be decided on the basis of law. The present matter is tried to be decided on the basis of law. It is easier to judge on the basis of law. But it can become difficult to, if the law is not clear or correct interpretation is not put on it.

287 Matters and ingredients, political, are often both not straight forward and are difficult. They can solve, create and complicate issues and problems. They can prove laudatory or abusive, soothing or agonising.

288 In such cases, the chances of political ingredients manifesting agonising characteristics may or may not be limited. One can only and sincerely hope that their play may be limited and dignified.

289 The present case involves the membership of 20 Parliamentarians who are the representatives of more than two crores of Indian citizens. They are elected by the People. In a Democracy, the verdict of the People has its own value.

290. Yet, the Representatives of the People are expected to come up to the expectations of the laws. The menace of floor crossing is not easy to handle. If it remains uncontrolled, it can destroy the parliamentary and democratic systems.

291. Therefore, actions are not taken in an ebullient and impulsive manner. But actions are taken to do justice. Those who are found to go against the law are subjected to punishment.

292. To judge is not easy.

293. To do justice, according to one's own light, is the only way available to one who has to decide and judge. That is tried to be done in this case.

### SOME SUGGESTIONS ON THE LAW THE TENTH SCHEDULE

294. The Tenth Schedule of the Constitution of India has served a great extent the purpose for which it has been brought into existence. It has some weak points and defects too. They are now thrown up and have become quite visible. They should not be allowed to continue in the body of the law.

### DEFINITIONS

295. It uses some words and phrases which are not defined. They should be properly defined to make the concepts contained in them more lucid and clear.

### SITUATIONS ENVISAGED

296. The law does not provide for coping up with the situations that arise in dealing with matters relating to defections. It should be made more comprehensive and should provide for possible situations which can crop up in interpreting and enforcing the law.

### Party activities outside the Legislature:

297. The law deals with defections in the Legislature. The defections in the Legislature are connected with the activities of political parties. The activities of the Members of the Parliamentary Party are governed by the Tenth Schedule, other provisions of the Constitution, other relevant laws and the Rules of Procedure followed by the Legislature.

298. The activities of the political parties outside the Legislature are not conducted according to the legal provisions for there are no laws available for the purpose. It is not easy or desirable to put them under rigid laws. The political parties should have freedom to conduct their activities as they like. But to control defections in the legislature, at times, it becomes necessary to have the activities of the political parties conducted in a predictable manner.

299. As to how it can be done should be examined. The Tenth Schedule can be made more comprehensive to cover some of the activities of the political parties to make it more effective. Or some other legislation can be agreed upon and passed by all concerned to make the political party's activities, more predictable.

### WHO SHOULD DECIDE

300. At present, the Speakers and Chairman decide

the anti-defection law cases.

301. Originally, their decisions were supposed to be final. Now, they are subject to the review by the judiciary. The provision in the law making the decisions final and non-reviewable by the judiciary has been struck down on the ground that it was not ratified by the requisite number of State Legislatures as it involved the ouster of the jurisdiction of the judiciary.

302. If it is decided to give finally to the decision given by the Speaker or the Chairman, the provision which was struck down, can be restored by taking recourse a procedure necessary in this respect.

303. Even then, the judiciary may claim inherent jurisdiction to review the decisions.

304. But, the inherent jurisdiction in the light of the provision in the law giving finality to the decision of the Speaker, or the Chairman may be used in very rare and exceptional cases which is different from allowing review in a frequent and regular manner.

305. Or we can amend the law and provide that the anti-defection law cases can be decided by a Supreme Court Judge or two Judges, if the cases related to the Parliament and by a High Court Judge or two Judges if the cases related to the State Legislatures.

306. The advantages in giving these cases to the Judiciary to decide are many.

307. The Judges are better equipped to decide legal matters. Anti Defection law cases have to be decided strictly according to the law. The Speaker or the Chairman may or may not be endowed with legal acumen and proficiency in law. He is certainly not going to be equal in this respect to the Judge of the Supreme Court or a High Court, whose main task is to hear legal matters and to decide them as per the law.

308. When the anti-defection law cases are heard by the Speaker or the Chairman, the Parties to the dispute appear before them and conduct the cases. They may or may not be fully acquainted with the procedures and principles of interpretation of facts and law. So, they can be of limited help in deciding these kinds of matters.

309. In a Court of Law, Lawyers can plead and conduct the cases, which is bound to help in disposing of the cases, in a better manner. The lawyers do appear before the Speaker or the Chairman as is done in the present case. But, allowing them to appear before the Speaker or the Chairman is different from allowing them to appear before a judge of the Supreme Court or a Judge of the High Court.

310. When the matters are conducted in front of the Speaker or the Chairman, the pleadings made, arguments advanced tend to be political rather than legal.

311. The Tenth Schedule is a part of the Constitution of India. The responsibility to interpret the Constitution of India is that of the Supreme Court or

the High Courts. It is, therefore, more apt to have the cases involving the interpretation of the Tenth Schedule decided by the Supreme Court or High Court Judges.

312. The Presiding Officers in the Legislatures in our country have considered this matter. They have their own views. They can again consider these matters and come to a final conclusion.

313. This aspect has been discussed in many other forums also. It should now be finally considered and decided as expeditiously as is possible.

#### THE WHIP :

314. All citizens of India can vote as they like. But, the Elected Representatives of the People have to vote as per the directions given to them by their party leaders.

315. This provision was introduced to control floor crossing. It may be necessary to have it in the law of anti-defection.

316. But is it necessary to ask the representatives of the People to vote in a particular manner in all cases ?

317. When a Motion of No-Confidence against the Government is discussed or when matters mentioned in the Manifesto are discussed, or some other very important matters are discussed, the Members of the Political Parties may be asked to take particular stands and directed to vote in a particular manner.

318. A list of matters in which votings can be directed to be done in a particular manner can be made a part of the law and can be followed by the Parties and their Members. On subjects mentioned in such matters, voting can be directed to be done in a particular manner.

319. In all other matters, it need not be directed to be done in a particular manner.

320. If provision of this nature are introduced in the Tenth Schedule, the anti defection law would achieve the purpose for which it is made and make the principles mentioned in the Chapter of Fundamental Rights and the Principles followed in Parliamentary and democratic systems in other countries more easily available to the Members of the Legislature.

#### OTHER PROVISIONS IN THE LAW :

321. There are some other provisions in the law which have been criticised and not liked by those who function in the Legislatures and the People also.

322. There are some provisions which need refining and fine tuning.

323. The law can be made more stringent and more effective by having some salutary provisions introduced in it.

#### Committee for the Purpose :

324. A Committee to look into the matters relating to the Tenth Schedule for above mentioned purposes and for other purposes also can and should be constituted in consultation with the representatives of the Executive at the Centre, the Executive at the State level, the Representatives of the Presiding Officers of the Legislatures and Legislators, the Jurists and the Officers well versed in the matters—Parliamentary and Legislative—can be asked to give a comprehensive report for overcoming the difficulties and defects of the law within a short period. Then the report can be acted upon expeditiously.

#### Can we Have Some other Device ?

325. Can we have some other device for these purposes?

326. Can we introduce provisions in the Constitution which can abviate the need to have a law of the nature we have now ?

327. Indications are that that is possible and can be done.

328. How exactly can it be done can not and need not be dealt with in detail at this place. What is to be perceived and remembered is that what is suggested is in the realm of possibility and should be examined and if found feasible, should be acted upon.

#### ORDER

1. It is held that the 20 Members of the Parliament who are signatories to the Application marked as 'D1' were the Members of the Parliament on 7-8-1992.

2. The request made by them in the Application is allowable and is allowed with respect to the sitting Members at this point of time.

3. Under the Tenth Schedule of the Constitution of India and the Members of Lok Sabha (Disqualification on the ground of Defection) Rules, 1985, it is decided—

(i) that S/Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan have incurred disqualification for being Member of the Lok Sabha and have ceased to be the Members of the Lok Sabha with effect from the date of this order.

(ii) that the petitions filed by Shri V. P. Singh against S/Shri Anadi Charan Das, Suryanarayan Yadav, Ramlakhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Abhay Pratap Singh and Upendranath Verma, MPs are dismissed.

- (iii) that the petition filed by Shri Srikant Jena against S/Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, and Satyapal Singh Yadav, MPs is dismissed.
- (iv) that the Petition filed by Shri Srikant Jena against S/Shri Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv Sharan Verma is dismissed.

on the ground that when they separated on 7-8-1992, they were sitting Members of the Lok Sabha and were equal to 1/3 Members of Janata Dal Legislature Party.

Copies of this order be forwarded to the Petitioners, the Persons/Members in relation to whom the Petitions are made and to the Leader of the Janata Dal Legislature Party in Lok Sabha.

SHIVRAJ V. PATIL  
Speaker, Lok Sabha.

Parliament House,  
New Delhi,  
Dated the 1st June, 1993

[No. 46/1/92/T]  
C. K. JAIN, Secretary-General